04 - युद्ध के बीच ईरान पर भारत का रुख सही

05 - चिली : शुष्क मिर्च में डेजर्ट का आकर्षण

06 - सार्वजनिक जीवन में आचरण और व्यवहार मर्यादित होना चाहिए

07 - विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक...

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 31 मार्च, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 207, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

महिला आरक्षण : 2029 लक्ष्य के पीछे क्या है सरकार की रणनीति?

यूसुफ़ अंसारी

इस हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में वृद्धि तथा महिला आरक्षण के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि सरकार लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव रख रही है। इनमें एक-तिहाई यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह राज्य विधानसभाओं में भी लगभग 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। यह क़दम नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) को 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू करने का रणनीतिक प्रयास है। लेकिन सवाल उठता है- क्या इस बढ़ोतरी पर विचार परिसीमन आयोग करेगा या गृह मंत्रालय? पूरी प्रक्रिया में क्या चुनौतियां, पेचीदगियां और भूमिकाएं हैं? और क्या 2027 के सात राज्यों के विधानसभा चुनाव नए परिसीमन के आधार पर होंगे?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें जनसंख्या के अनुपात में तय होती हैं, लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई थी। 84वें संशोधन (2001) ने इसे 2026 तक बढ़ा दिया। अब 2026 के बाद नया परिसीमन अपेक्षित था, जो 2027 की जनगणना पर आधारित होना था। लेकिन सरकार ने 2011 की जनगणना को आधार बनाकर प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया है।

शाह की बैठक में सुझाया गया कि महिला आरक्षण को जनगणना और पूर्ण परिसीमन से अलग कर दिया जाए। लोकसभा की कुल सीटें 543 से 816 (50 प्रतिशत बढ़ोतरी) की जाएंगी, ताकि मौजूदा 543 सीटों में कोई कटौती न हो और नई 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकें। राज्यवार अनुपात वही रहेगा–उत्तर प्रदेश को 80 से 120, महाराष्ट्र को 48 से 72, पश्चिम बंगाल को 42 से 63, बिहार को 40 से 60 और तमिलनाडु को 39 से 59 सीटें मिल सकती हैं। विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी प्रस्तावित है। नई व्यवस्था 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू होगी।

यह प्रस्ताव इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि मूल अधिनियम में महिला आरक्षण को 2027 जनगणना के बाद के परिसीमन से जोड़ा गया था, जिससे क्रियान्वयन 2034 तक टल सकता था। अब 2011 डेटा से परिसीमन कर 2029 तक आरक्षण लागू करने का लक्ष्य है।

संवैधानिक संशोधन से लेकर अंतिम अधिसूचना तक सीटों की कुल संख्या बढ़ाने और परिसीमन की प्रक्रिया बहु-चरणीय है। सबसे पहले दो संविधान संशोधन विधेयक लाने होंगे–एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव के लिए, दूसरा परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 में। इनके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है, साथ ही कुछ राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी। गृह मंत्रालय इन विधेयकों को तैयार करेगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति की अधिसूचना से नया परिसीमन आयोग गठित होगा। आयोग 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित करेगा, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करेगा, अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटें तय करेगा तथा महिला आरक्षण के लिए रोटेशन (तीन चुनावों तक आरक्षित, फिर खुली) लागू करेगा। आयोग का ड्राफ्ट प्रस्ताव सार्वजनिक किया जाएगा, आपत्तियां ली जाएंगी, सुनवाई होगी और अंतिम आदेश राष्ट्रपति द्वारा गजट में प्रकाशित होगा। यह आदेश कानून का दर्जा रखता है और किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

चुनाव आयोग परिसीमन में सीधे शामिल नहीं होता, लेकिन वह आयोग को डेटा उपलब्ध कराता है और नए क्षेत्रों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाएगा। सरकार 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रख रही है।

परिसीमन आयोग यह अर्ध-न्यायिक, स्वायत्त निकाय है। इसका गठन परिसीमन अधिनियम के तहत होता है। आयोग में एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज (अध्यक्ष), मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य–सीटों की संख्या तय करना, सीमाएं खींचना, SC/ST आरक्षण तय करना और अब महिला आरक्षण लागू करना। यह जनसंख्या समानता (लगभग समान आबादी वाले क्षेत्र) सुनिश्चित करता है। 1952, 1963, 1973 और 2002 में चार आयोग गठित हो चुके हैं। नया आयोग 2011 डेटा पर काम करेगा, लेकिन मौजूदा राज्यों के बीच अनुपात बनाए रखेगा।

गृह मंत्रालय नीतिगत और क्रियान्वयन की अगुवाई करता है। संघीय संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी ले रहा है–दक्षिणी राज्यों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी एक भी सीट कम नहीं होगी।

चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करता है, नए क्षेत्रों में मतदान केंद्र स्थापित करता है और चुनाव कराता है। अंतिम रूप से EC ही नए परिसीमन के आधार पर चुनाव घोषित करेगा।

यह प्रक्रिया कई चुनौतियों से भरी है। सबसे बड़ी उत्तर-दक्षिण विभाजन की है। दक्षिणी राज्य (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि) ने जनसंख्या नियंत्रण किया, लेकिन उत्तर (यूपी, बिहार) की आबादी ज्यादा बढ़ी। अगर 2011 डेटा से भी परिसीमन होता है तो दक्षिण को अनुपात से कम प्रतिनिधित्व मिलने का डर है। हालांकि सरकार ने प्रो-रेटा बढ़ोतरी का आश्वासन दिया है, फिर भी राजनीतिक आक्रोश है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहले ही इस पर सर्वदलीय बैठक बुला चुके हैं।

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ने शाह की बैठक का बहिष्कार किया और पूर्ण सर्वदलीय बैठक की मांग की। ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना की मांग भी उठ रही है। संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी है, इसलिए सहमति अनिवार्य है।

अभी जनगणना 2027 चल रही है, लेकिन उसका इंतजार न करके 2011 का डेटा इस्तेमाल करने से वर्तमान प्रवासन और जनसांख्यिकी को नजरअंदाज करने का खतरा है। 2027 में सात राज्यों (राज्यसभा, राष्ट्रपति चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव) के चुनाव प्रस्तावित हैं। लेकिन नए परिसीमन की प्रक्रिया जून 2026 से शुरू होकर 2029 लोकसभा चुनावों के लिए लक्षित है। राज्य विधानसभाओं के लिए भी समान प्रक्रिया चलेगी, लेकिन इतने कम समय में 2027 तक पूरा होना संभव नहीं लगता। इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव पुरानी सीटों यानी 2008 के परिसीमन पर ही होंगे। नई व्यवस्था 2029 या उसके बाद की विधानसभा चुनावों (2026-27 के बाद वाले) से लागू हो सकती है। सीटों का विस्तार लोकतंत्र को अधिक समावेशी बना सकता है–महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। लेकिन उत्तर-दक्षिण असंतुलन, विपक्षी अविश्वास और प्रक्रियागत देरी अगर नहीं सुलझी तो यह संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। अंततः यह बदलाव भारत की बदलती जनसांख्यिकी को स्वीकार करने का अवसर है, लेकिन इसमें राजनीतिक परिपक्वता और सर्वदलीय सहमति ज़रूरी है। अगर सरकार इसमें कामयाब होती है तो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण का सपना साकार हो जाएगा।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

जो हथियार उठाएगा, उसे हर हाल में कीमत चुकानी होगी

● शाह ने कहा- अब बस्तर से लाल आतंक लगभग खत्म ● वामपंथियों ने भोले-भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 'नक्सल मुक्त भारत' मुद्दे पर चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा- जो लोग पूरी व्यवस्था को नकार कर हथियार उठा लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हथियार उठाने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। शाह ने कहा- सालों से भोले-भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा गया। वामपंथियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए भोले भाले आदिवासियों को बहकाया। कांग्रेस ने आजादी के बाद 75 साल में 60 साल राज किया। फिर आदिवासी

विकास से क्यों बच गए। शाह ने कहा- कांग्रेस ने 60 साल के दौरान आदिवासियों तक घर, स्कूल, मोबाइल टॉवर नहीं पहुंचने दिया और अब हिसाब मांग रहे हैं। अपने गिरेबान में झांककर देखिए। जो लोग नक्सलवाद की वकालात करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं ये सब 1970 से अब तक क्यों नहीं हुआ था। संसद में आज नक्सलवाद पर चर्चा सरकार की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले हो रही है। शाह कई बार 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं। बस्तर से नक्सलवाद लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। बस्तर के हर एक गांव में स्कूल खोलने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस क्षेत्र के हर गांव में राशन की दुकान खोलने के लिए एक मुहिम शुरू की गई।

60 साल तो कांग्रेस सरकार में रही, किया क्या

70 में से 60 साल तो सरकार कांग्रेस की रही, फिर क्यों विकास नहीं हुआ। आपने क्यों नहीं किया विकास आज आप हिसाब मांग रहे हो। मैं पूरा बताऊंगा। वहां करोड़ों लोग गरीबी में वर्षों तक जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की। 20 हजार युवा मारे गए, कई दिव्यांग बन गए और उन तक विकास नहीं पहुंचा। कौन जिम्मेदार है। क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत को इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं, एक आइडियोलॉजी है, जिसे एक राष्ट्रपति चुनाव के कारण इंदिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया। मनमोहन ने कहा था– माओवादी देश की सबसे बड़ी समस्या : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकारा था कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में देश की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी समस्या माओवादी है। 2014 में बदलाव हुआ।

शरद की सुबह

सपना केवल
सपना नहीं
सत्य की सुंदरता है
जो जीवन में
सौंदर्य को
रचती रहती है
अनुक्षण

उसका घर
प्यार का घर है
जहां कोयल गाती है
चिड़िया चहकती है
यही कारण है
उसका घर
औरों से अधिक
न्यारा है

उसमें एक जादू है
जो सबकी आँखों को
रस में भिगो देता है

उसके दिल में
बहती रहती है
स्नेह की नदी
जिसमें डूब डूब कर
सब रसमग्न होते रहते हैं

उसका जीवन
कविता का जीवन है
जिसका
अपना राग है
अपना छंद है
अपनी लय है

उसके इस कवितामय
जीवन में
प्यार है
प्यार है
प्यार है
बस।

-दुर्गाप्रसाद झाला

ट्रंप की जिद से 'संकट' में दुनिया!

● ईरान पर हमला कर आजाद कर दिया परमाणु बम वाला 'जिन्न' ● ट्रंप की नीतियों ने वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ बढ़ाई ● ईरानी शासन आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार पर दृढ़ होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान में शुरू हुए अमेरिका-इजरायल के युद्ध को आज 31 दिन हो गए हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमेशा की तरह ट्रंप अपने बयानों से पलट रहे हैं, लेकिन वह एक बात पर अडिग हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। इस एक जिद ने दुनिया को एक ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया है, जहां जल्द ही न्यूक्लियर पावर बनने की रेस शुरू होने वाली है। ट्रंप के इस कदम ने एक ऐसा न्यूक्लियर जिन्न बाहर ला दिया है, जिसे वापस बोतल में डालना मुश्किल होगा। अपने मकसद को हासिल करने के लिए अमेरिका ने पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होंगे, तो मिडिल ईस्ट में कभी भी शांति नहीं हो पाएगी। ट्रंप का ये डर सिर्फ उनके दिमाग की उपज ही नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक, ईरान ने 408.6 किलोग्राम यूरेनियम को 60 फीसदी तक एनरिच कर लिया है।

ट्रंप की मनमौजी से दुनिया परेशान

इन उपजी स्थितियों के लिए सिर्फ ईरान का पागलपन ही जिम्मेदार नहीं है। अमेरिका और खासकर ट्रंप ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु संधि की और फिर ट्रंप ने हाथ पीछे खींच लिए। ट्रंप ईरान को बातचीत के मंच पर भी लेकर आए और फिर उसी दौरान उस पर हमला कर दिया। इससे दुनिया को यह संदेश गया कि मनमौजी अमेरिका के साथ कोई समझौता करना बेकार है, जहां कोई भी प्रशासन अपने से पहले वाले प्रशासन द्वारा किए गए वादों से पीछे हट सकता है। ईरान के लिए न्यूक्लियर पावर अब सिर्फ अपने दुश्मनों के बराबर ओहदे तक पहुंचने की कोशिश भर नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर वहां के कट्टरपंथी शासन के खिलाफ उठने वाली आवाजों को हमेशा के लिए खत्म करने का एक जरिया भी बनेगा।

अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है ईरान

ईरान ने मिडिल ईस्ट में खुद को शक्तिशाली बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके पास करीब 2500 बैलेस्टिक मिसाइलें हैं, जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा हैं। वह पूरे इलाके में आतंकवादी प्रॉक्सी को समर्थन देता है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता में इजाफा हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान पर अमेरिका का हमला भले ही कुछ समय के लिए उसकी न्यूक्लियर पावर बनने की महत्वाकांक्षाओं को धीमा कर दे, लेकिन अगर वहां का शासन इस युद्ध में बच गया, तो वह परमाणु हथियार हासिल करने के लिए और भी दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसके पास यही एकलौता साधन होगा।

जनगणना 2026 में 33 सवाल पूछेगी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए 33 सवालों वाली नई प्रश्नावली जारी की है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसमें इंटरनेट, एलपीजी, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ बदलते सामाजिक ढांचे को समझने पर खास जोर दिया गया है। इस प्रश्नावली को 2011 की पिछली जनगणना के बाद भारतीय समाज में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें घर के प्रकार, स्थान सब शामिल होगा।

दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा

जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होगा और दूसरा चरण जनसंख्या गणना, जो 1 फरवरी 2027 से शुरू होगी। यह भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी, जो देश में नीति निर्माण और विकास योजनाओं के बारे में है।

विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री यादव

राजनीति में विनम्रता, मर्यादा और अनुशासन आवश्यक

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राजनीति में विनम्रता, मर्यादा और अनुशासन आवश्यक है। वे ही इस क्षेत्र में सक्रिय और सफल हो सकते हैं, जिनमें जनसेवा और जनकल्याण की भावना हो। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से राजनीति में आने वाले लोगों के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जनप्रतिनिधियों के लिए जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील होना, अध्ययनशील होना, तनाव प्रबंधन में दक्ष होना और जनहित के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करना आवश्यक है। कोई समस्या आने पर जनप्रतिनिधि का व्यवहार और समस्या निराकरण के लिए उनका प्रबंधन कौशल, उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। सकारात्मक और समाज हित की गतिविधियों और विकास कार्यों के लिए हमें दलगत मतभेदों से ऊपर उठकर सोचना और कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में आयोजित युवा विधायकों के दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा के विधान परिषद हाल में हुआ कार्यक्रम वंदे मातरम् के गान के साथ आरंभ हुआ। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार विशेष रूप से उपस्थित थे। सम्मेलन में राष्ट्रकुल संसदीय संघ (भारत क्षेत्र 6) के तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के 45 वर्ष आयु तक के विधायक सम्मिलित हुए।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में युवा जनप्रतिनिधियों की अहम जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में युवाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र की व्यवस्था नहीं, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुता पर आधारित एक व्यापक व्यवस्था है। भारत का लोकतंत्र नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही मजबूत होता है। उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के 25 नवंबर 1949 के संविधान सभा के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लागू करने वाले लोग कितने प्रतिबद्ध और नैतिक हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 31 मार्च 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

कनाडा में हिंदुओं को खालिस्तानी समर्थकों ने फिर से दी धमकी

● 5 को मंदिरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान, एचसीएफ ने कहा- झुकेंगे नहीं

लुधियाना (एजेंसी)। खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में फिर से हिंदुओं को धमकियां देनी शुरू कर दी। खालिस्तान चरमपंथी संगठनों ने 5 अप्रैल 2026 को 2 बड़े हिंदू मंदिरों के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद रैलियां और प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। खालिस्तान समर्थक ब्रैम्पटन के त्रिवेणी मंदिर और सरे के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। खालिस्तानियों ने बकायदा सोशल मीडिया पर इन मंदिरों के गेट पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं, हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने इस पर तुरंत सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है हमारे मंदिर पूजा के पवित्र स्थान हैं, ये प्रदर्शन के मैदान नहीं हैं। हम धमकी के आगे नहीं झुकेंगे।

एचसीएफ ने पूरे कनाडा की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इन चरमपंथियों को रोको, वरना हिंदू समुदाय का भरोसा कनाडा की पुलिस और सरकार से टूट जाएगा। एचसीएफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साफ ऐलान किया कि 5 अप्रैल को ब्रैम्पटन के त्रिवेणी मंदिर और सरे के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली जाएगी। ये रैलियां सीधे मंदिर के गेट पर होगी। खालिस्तान समर्थकों ने धमकी देते हुए कहा है कि हिंदू जब पूजा करने आएंगे तो उन्हें नारे सुनने पड़ेंगे, धक्का-मुक्की हो सकती है। खालिस्तान समर्थक कनाडा में पहले भी मंदिरों के बाहर माहौल खराब करने की कोशिश कर चुके हैं। खालिस्तान समर्थक एसजेएफ की तरफ से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट। खालिस्तानियों की धमकी के बाद एचसीएफ का कहना है कि ये कोई शांतिपूर्ण विरोध नहीं, बल्कि जानबूझकर उकसावे की साजिश है। मंदिर को राजनीतिक स्टेज बनाने की कोशिश की जा रही है।

नेवी कर्मचारी ने प्रेमिका के तीन टुकड़े किए, सिर जलाया

● एक हिस्सा बेड के नीचे, दूसरा फ्रिज में रखा, थाने पहुंचकर अपराध कबूला

विशाखापत्तनम (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक शादीशुदा नेवी कर्मचारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने शव के 3 टुकड़े किए। एक हिस्सा फ्रिज में छिपा दिया, दूसरा बोरे में भरकर बेड के नीचे रख दिया और तीसरा यानी सिर को सुनसान इलाके में ले जाकर जला दिया। वारदात के समय पत्नी मायके गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी चिंतादा रविंद्र (35) नेवी कर्मचारी हैं। वह आईएनएस डेगा में तैनात है। रविंद्र ने रविवार दोपहर अपनी 29 साल की प्रेमिका मोनिका को घर बुलाया था। शाम के समय दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने हत्या कर दी। हत्या के

बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर अपराध कबूल कर लिया। पुलिस के जांच में सामने आया कि रविंद्र ने मोनिका की चाकू से हत्या की। रविंद्र और मोनिका की मुलाकात 2021 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच संबंध बने। वे विशाखापट्टनम में अलग-अलग जगहों पर मिलते थे। पुलिस के मुताबिक रविंद्र का दावा है कि मोनिका ने उससे 3.5 लाख रुपए लिए थे। वह अक्सर रिश्ते का खुलासा करने की धमकी देती थी। वारदात के वक्त रविंद्र की पत्नी कुछ दिन पहले विजयनगरम स्थित अपने मायके गई हुई थी। इसी दौरान उसने मोनिका को घर बुलाया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। रविंद्र हत्या के इरादे से चाकू खरीदने दुकान में गया था, जब वहां चाकू नहीं मिला तो ऑनलाइन मंगाया। घटना के बाद आरोपी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपराध कबूल कर लिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर और फ्रिज से शव के टुकड़े बरामद हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महावीर जयंती पर श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महावीर जयंती पर श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल के दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन समाज द्वारा संयुक्त तत्वावधान में निकाली जा रही भगवान महावीर स्वामी की शोभायात्रा का इतवारा पहुंचकर स्वागत कर यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज सहित अन्य मुनिगण को श्रीफल भेंट

कर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप, प्रदेश महामंत्री श्री राहुल कोठारी, दिगम्बर पंचायत कमेटी के अध्यक्ष श्री पंकज जैन, सुपारी और श्वेताम्बर समाज के अध्यक्ष श्री राजेश तांतेड़ उपस्थित थे।

ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी, युवक की मौत

दतिया-भांडेर रोड पर हादसा; माता-पिता घायल, ध्वार वाली माता के दर्शन को जा रहे थे

दतिया (नप्र)। दतिया में भांडेर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जबकि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा दतिया-भांडेर रोड पर उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी।

मृतक की पहचान संदीप अहिरवार (20) के रूप में हुई है। घायल पिता राकेश अहिरवार और मां भारती अहिरवार हैं। जो मूल रूप से शिवपुरी जिले के राजपुरदयाल गांव के निवासी हैं और वर्तमान में दतिया की सिद्धार्थ कॉलोनी में रह रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, पूरा परिवार बाइक से भांडेर स्थित ध्वार वाली माता के दर्शन करने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया। वहीं पिता राकेश की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है, जबकि मां भारती का इलाज जिला अस्पताल में जारी है।

न्यूजीलैंड के साथ बड़ी डील की तैयारी में भारत

● पीएम मोदी की यात्रा जल्द, एफटीए पर हो सकता है साइन

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर महत्वपूर्ण चर्चा और प्रगति की उम्मीद है। यात्रा की तारीखों की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित न्यूजीलैंड यात्रा को नई गति मिली है। दोनों पक्षों ने पीएम मोदी की आगामी यात्रा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। न्यूजीलैंड ने इस यात्रा को लेकर प्रबल उत्साह व्यक्त किया और कहा कि यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी जाने की

संभावना है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल, मंत्रियों ने हाल ही में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए व्यापार समझौते की वार्ताओं पर चर्चा की।

मई में कनाडा जाएंगे पीयूष गोयल

इसी क्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मई 2026 में कनाडा का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे व्यापार वार्ताओं और मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। गोयल की यह यात्रा भारत-कनाडा के बीच व्यापार संबंधों को नई गति देने और आर्थिक साझेदारी को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन दोनों दौरों से भारत की व्यापक व्यापार कूटनीति को बल मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रमुख साझेदार देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंध स्थापित करना शामिल है। कैमरून के याउंडे में चल रही विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान पीयूष गोयल उपस्थित थे।

● यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जल्द बढ़ेगा मानदेय

योगी बोले-स्मार्ट सैलरी के लिए विभाग प्रस्ताव तैयार करे, 69 हजार स्मार्टफोन बांटे

लखनऊ (एजेंसी)। सीएम योगी ने सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा- अगर

आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने विभाग से कहा है कि जल्द मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव लाएं। सम्मानजनक मानदेय दें। सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। दरअसल, प्रदेश में 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इन्हें 8000 रुपए महीना मानदेय मिलता है। ऐसे ही 1.39 लाख सहायिकाओं को 4000 रुपए महीना मानदेय मिलता है। सूत्रों के मुताबिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4000 और सहायिकाओं का मानदेय 3000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। योगी सरकार ने पिछली सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- 2017 के पहले पोषाहार का वितरण उत्तर भारत का सबसे बड़ा शराब माफिया करता था।

● **आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानजनक मानदेय मिलेगा-** योगी ने कहा कि पहले जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी एजेंसियां थीं, वह कोई माफिया या नेता संचालित करते थे। कर्मचारियों का शोषण करते थे। सरकार से कर्मचारी के लिए 10-12 हजार पाते थे, लेकिन पांच या छह हजार देते थे। वह सरकार से भी लेते थे, कर्मचारी से भी लेते थे। इसके अलावा नियुक्ति के समय भी पैसा लेते थे। योगी ने कहा कि अब हमने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक कॉरपोरेशन गठित किया है। मैंने विभाग को बुलाकर सख्ती से कह रखा है कि अप्रैल से इस व्यवस्था को हर हाल में लागू करने की तैयारी करें।

पटना यूनिवर्सिटी में नीतिश के कार्यक्रम में भारी हंगामा

● छात्र बोले- हम कैंपस को बीजेपी ऑफिस नहीं बनने देंगे

पटना (एजेंसी)। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में एकेडमिक भवन और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने पटना डीएम चोर है और डिप्टी सीएम गो बैक के नारे भी लगाए। सीएम के पहुंचने से पहले भी छात्र नेता नारेबाजी कर रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर का कहना है कि इस कार्यक्रम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यहां तक कि कुलपति को भी इसके लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है।

हंगामे के चलते सीएम ने 7 से 8 मिनट में अपना कार्यक्रम खत्म किया और वहां से निकल गए। इस दौरान मुख्यमंत्री कैंपस में जहां-जहां गए छात्र नेता उनके पीछे-पीछे जाते रहे। छात्रों ने कहा, आप अपने लिए खड़े होइए सर, हमलोग आपके साथ हैं। यूनिवर्सिटी को हम बीजेपी का कार्यालय नहीं बनने देंगे। छात्रों का कहना है सीएम को मिलने नहीं दिया गया। वो गए, लेकिन उनको बिना मिले भेज दिया गया।

चीनी वैज्ञानिकों ने समुद्र में बनाया 'तैरता हुआ द्वीप'

● 10000 मीटर गहराई तक करेगा खोज, पहला रिसर्च स्टेशन लॉन्च

बीजिंग (एजेंसी)। चीन के वैज्ञानिकों ने समुद्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे दुनिया में अब तक कोई देश नहीं कर सकता है।

चीनी वैज्ञानिकों ने शनिवार को शंघाई में दुनिया का पहला समुद्री रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे ओपन-सी फ्लोटिंग आइलैंड नाम दिया गया है। यह गहरे समुद्र में काम करने वाली वाली रिसर्च फैसिलिटी है, जो हर मौसम में इस्तेमाल किए जाने के लिए बनाई गई है। समुद्र के कठोर हालात में लगातार काम करने के लिए डिजाइन किया गया यह प्लेटफॉर्म कई तरह की वैज्ञानिक गतिविधियों में मदद करेगा, जिसमें एडवांस समुद्री उपकरणों का विकास, समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री विज्ञान पर व्यापक शोध शामिल है।

इस बड़ी वैज्ञानिक सुविधा में तीन मुख्य हिस्से हैं- मुख्य सुविधा प्लेटफॉर्म, जहाज पर बनी प्रयोगशालाएं और तट आधारित सहायता।

मुख्य सुविधा प्लेटफॉर्म एक नया सेमी-सबमर्सिबल ट्विन हल (आधा डूबा हुआ दोहरे ढांचा वाला) डिजाइन है। यह सैकड़ों टन वजनी गहरे समुद्र के उपकरणों की पूरी तरह से टेस्टिंग करने और 10000 मीटर तक की समुद्री गहराई पर वैज्ञानिक खोज और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सहायता करने में सक्षम है।

लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है भारत

● सरकार के आयुष मंत्रालय ने नया योग प्रोटोकॉल किया शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। आयुष मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गैर-संक्रामक बीमारियों और जोखिम वाले समूहों के लिए एक व्यापक योग प्रोटोकॉल शुरू किया है। इस महीने की शुरुआत में योग

महोत्सव 2026 के दौरान आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा शुरू की गई इस पहल को जीवनशैली से जुड़ी विभिन्न बीमारियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जा रहा है। यह पहल आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में स्थित केंद्र द्वारा विकसित की गई है।

● **जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से मिलेगी राहत-** संस्थान के एक अधिकारी ने बताया कि भारत में आज मधुमेह, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, श्वसन संबंधी बीमारियां और मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। हाल के अनुमानों के अनुसार, देश में होने वाली लगभग दो-तिहाई मौतें इन्हीं बीमारियों के कारण होती हैं। यह जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की ओर स्पष्ट बदलाव का संकेत देती है।

● **30 से 60 मिनट तक रोजाना योग की सिफारिश-** अधिकारी ने बताया कि गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु दर में प्रतिवर्ष हो रही वृद्धि को देखते हुए निवारक उपायों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसी संदर्भ में नए योग प्रोटोकॉल का महत्व बढ़ गया है। वैज्ञानिक प्रमाणों और नैदानिक दृष्टिकोण पर आधारित यह मॉड्यूल 30 से 60 मिनट के दैनिक सत्र की सिफारिश करता है, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और विश्राम तकनीकें शामिल हैं। इसे विभिन्न फिटनेस स्तरों और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुरूप बनाया गया है। इस पहल का उद्देश्य योग को बढ़ावा देना है।

गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, पूरा देश संकट में

महंगाई पर प्रियंका गांधी का मोदी पर वार, जंग पर बहस की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केरल की जनता को अच्छी तरह पता है कि असली गठबंधन किसके बीच है और सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस महासचिव ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर संसद में बहस की मांग करते हुए कहा कि इसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, हम लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं क्योंकि पूरा देश संकट में हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं और चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। और ज्यादा संकट आ रहा है। इसलिए हम लोग बहस चाहते हैं तो उम्मीद है कि सरकार बहस कराएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि युद्ध जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपनी तैयारियों को स्पष्ट करने की रणनीति पर बात करने को कहा।

बिहार में अब होगा

बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया तय !

● जेडीयू से बनेंगे 2 डिप्टी सीएम, एनडीए में मंथन शुरू ● खरमास के बाद 15 अप्रैल तक नई सरकार है संभव

पटना (एजेंसी)। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने को ले एनडीए में मंथन शुरू है। ऐसी संभावना है कि खरमास के बाद 15 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। अगले महीने की 10 अप्रैल को नीतिश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। नई सरकार के गठन होने तक मुख्यमंत्री का कामकाज नीतिश कुमार ही देखते रहेंगे। बिहार में नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने को ले एनडीए में मंथन शुरू है। पिछले दिनों एनडीए के घटक दल हम के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम लिया था। लोजपा (रामविलास) की ओर से भी इसी तरह का वक्तव्य आया था। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने भी अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान मंच से भाजपा नेता की पीठ पर हाथ रख इशारा किया था।

खरमास खत्म होने के बाद ही नई सरकार

एनडीए घटक दल के नेताओं का कहना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि खरमास खत्म होने के बाद ही बिहार में नई सरकार अस्तित्व में आएगी। खरमास 14 अप्रैल को खत्म हो रहा। वहीं, नीतिश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद वह 11 अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कार्यकारी व्यवस्था होने तक वह बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

तेहरान पर हमले में नेवी चीफ तंगसिरी की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान ने सोमवार को रिवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना प्रमुख अलीरेजा तंगसिरी की मौत की पुष्टि की। इससे पहले

इजरायल ने गुरुवार को दावा किया था कि उसने ईरान की नौसेना में रियर एडमिरल तंगसिरी को मार गिराया है। सोमवार को गार्ड की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि तंगसिरी अपनी चोटों की गंभीरता के कारण अल्लाह की शरण में चले गए। इस बयान को सरकारी टेलीविजन पर पढ़ा गया। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, बयान में तंगसिरी के प्रयासों की सराहना की गई।

लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा शब्बीर अहमद लोन अरेस्ट

● दिल्ली, तमिलनाडु में आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा था

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक, शब्बीर दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती करने की तैयारी में था। यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ऑपरेट हो रहा था। साल 2007 में भी दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों में लोन को गिरफ्तार किया था।

परिक्रमा

विधायक अपने क्षेत्र में बना सकेंगे आदर्श कृषि ग्राम

अरुण पटेल

लेखक सुबह सबेरे के प्रबंध संपादक हैं

मध्यप्रदेश में विधायक अब अपने विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श कृषि ग्राम बना सकेंगे। यह जिम्मेदारी उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी। डॉ. यादव का पूरा ध्यान इस समय मध्यप्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आदर्श राज्य के रुप में मध्यप्रदेश की छवि को निखारना है और इसके लिए वह कोई कदम उठाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। किसानों को भी वे अपने साथ जोड़ रहे हैं और औद्योगीकरण की गति को बढ़ा कर राज्य को एक नई पहचान देने के अभियान में भिड़े हुए हैं। उनके प्रयासों से ही राष्ट्रीय पटल से लेकर मध्यप्रदेश तक में एक अभियान छिड़ा हुआ है जिसका मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें उनकी फसल का बाजिव मूल्य दिलाना है ताकि प्रदेश का विकास तेज गति से हो सके। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस समय मध्यप्रदेश की छवि निखार कर उसे तेजी से विकसित होने वाले प्रदेशों की श्रृंखला में अव्वल बनाने का पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश सरकार इन दिनों कृषक कल्याण वर्ष बना रही है जिसमें किसानों और खेती में उपयोग आने वाले उपकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चूंकि यह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में होना है इसलिए एक गांव गोद लेने के लिए विधायकों से कहा गया है और इसे विधायक ग्राम में रुप में विकसित किया जायेगा। इससे एक फायदा तो यह होगा कि कृषि उत्पादन तो बढ़ेगा ही लेकिन साथ ही औद्योगिक फलक पर भी राज्य अपनी पहचान बनाने की दिशा में सधे हुए कदमों से आगे बढ़ेगा। जो आदर्श कृषि ग्राम होगा उसमें किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें परम्परागत खेती के साथ-साथ पशुपालन, उद्यानिकी फसल उत्पादन और प्राकृतिक खेती से जोड़ा जायेगा। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती को हतोत्साहित करने के साथ उड़द की खेती करने को प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य सरकार किसानों को यह भी बताने की कोशिश कर रही

है कि पहली बार प्रदेश में उड़द पर सरकार 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। विधायकों को यह भी भरोसा दिलाया गया है कि उन्हें अलग से बजट भी आवंटित किया जायेगा ताकि वह अपने क्षेत्र और स्थानीय खेती की समस्याओं को हल कर सकें। विधायकों को कृषक कल्याण के लिए विधानसभा क्षेत्रानुसार कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। इसके लिए मेला और कृषक संगोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र में किसान रथ भ्रमण कराया जायेगा, बैलगाड़ी व ट्रैक्टर रेस का भी आयोजन किया जायेगा साथ ही जैविक उत्पादों के वितरण के लिए विशेष हाट-बाजारों का भी आयोजन किया जायेगा।

विधायक अपने क्षेत्र के सभी किसानों को एग्रीटेक में शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग कराने के साथ ही ई-विकास विपणन और कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली के माध्यम से सौ प्रतिशत वितरण कराना भी सुनिश्चित करायेंगे। यह एक ऐसा कार्य होगा जो कि आसान नहीं होगा, लेकिन इसे मूर्तरुप देने के लिए विधायकों को पूरे समर्पण के साथ जुटना होगा। राष्ट्रकुल संसदीय संघ भारत क्षेत्र-6 के तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों का दो दिवसीय शिक्षण सम्मेलन 30 और 31 मार्च को भोपाल के विधानसभा भवन में आयोजित हो रहा है। इसमें मध्यप्रदेश के 18, छत्तीसगढ़ के 15 और राजस्थान के 22 विधायक शामिल होंगे। 30 मार्च को ही लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने में युवा विधायकों की भूमिका पर मंथन किया जायेगा। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमण सिंह भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन 31 मार्च को 'विकसित भारत 2047 युवा विधायकों के दायित्व और चुनौतियों' विषय पर भी मंथन होगा। हर दिन विभिन्न सत्रों के अलावा एसआईटी पुणे के चेयरमेन डॉ. राहुल वी. कराड़ का उद्बोधन भी होगा।

और यह भी

धार में ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला खुदाई स्थल की अंतिम सुनावाई से पहले हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने परिसर का निरीक्षण किया। चूंकि इस मामले की अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल को होने वाली है इसलिए उससे पूर्व न्यायाधीशों का निरीक्षण काफी अहम् माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत की है। लगभग एक घंटे तक उन्होंने भोजशाला परिसर का अवलोकन किया। यह दौरा गोपनीय था, निरीक्षण के दौरान कलेक्टर, एसपी और एएसआई के अधिकारियों को प्रवेश दिया गया। जजों ने प्रवेश द्वार से ही स्थल तक की वास्तुकला और खम्भों की नक्काशी और शिलालेखों की प्राचीन लिपि का अध्ययन किया। एएसआई द्वारा की गयी खुदाई स्थल की भी उन्होंने जानकारी ली। इस प्रकार अब लगता है कि हर साल भोजशाला में होने वाली नमाज और पूजा को लेकर जो स्थिति पैदा होती है शायद उसका स्थायी निराकरण निकल सके।

इकबाल मैदान विवाद में बढ़ी तकरार

विरोध में उतरा मुस्लिम संगठन, कहा- एनएचआरसी सदस्य के बयान को बताया भड़काऊ

भोपाल (नप्र)। भोपाल में ऐतिहासिक इकबाल मैदान का नाम बदलने को लेकर विवाद तेज हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के बयान के विरोध में सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने मैदान में प्रदर्शन किया और बयान को भड़काऊ बताया।

समिति के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा कि इस तरह के बयान देश में तनाव का माहौल पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लामा मुहम्मद इकबाल विश्व प्रसिद्ध शायर रहे हैं, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा तराना लिखा, जिसे आज भी देशभर में गर्व के साथ गाया जाता है। ऐसे में उनके नाम पर बने मैदान को लेकर इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है।

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो. दानिश खान ने इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश बताते हुए कहा कि इस तरह के मुद्दे समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष तनवीर कुरैशी, मीडिया प्रभारी आरिफ खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े नामों को बदलने के बजाय सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वहीं, शमशुल हसन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मानवाधिकार आयोग जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आयोग के सदस्य को मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर बोलना चाहिए, न कि धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े विवादों को हवा देनी चाहिए।

प्रियंक कानूनगो ने कहा था- इकबाल मैदान कलंक है- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें वे इकबाल की फोटो पोस्ट करते हुए कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के नाम का प्रस्ताव रखने वाले इकबाल के नाम पर भोपाल में कोई मैदान होना चाहिए। यह हमारे माथे पर कलंक है।

एक्स पर वीडियो पोस्ट करने के साथ कानूनगो ने यह भी ट्वीट किया है कि पाकिस्तान बनाये जाने का प्रस्ताव लिखने वाले इकबाल के नाम पर हमारे भोपाल में इकबाल मैदान होना हमारे माथे पर कलंक है। भोपाल का नवाब भोपाल की गरीब जनता का हमारे पूर्वजों का खून चूस-चूस कर इस इकबाल को उसके ऐशो आराम के लिए हजारों रुपया वजीफा में देता था। हम इस कलंक को मिटाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देंगे। रिपोर्ट के अनुसार शायर अल्लामा इकबाल चार बार भोपाल आए थे और यहां लगभग छह महीने बिताए थे, इस दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध शायरी की रचना की थी। उनकी याद में भोपाल में इकबाल मैदान है, जहां की दीवारों पर उनकी शायरी अंकित है। यह मैदान नवाबों के दौर की याद दिलाता है और एक समय यह सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था।

1930 में इकबाल ने रखा था अलग मुस्लिम राज्य का विचार

अल्लामा मुहम्मद इकबाल ने सबसे पहले भारत के उत्तर-पश्चिम में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में इस अलग राष्ट्र की अवधारणा (कांसेप्ट) रखी थी। इकबाल ने अपने प्रसिद्ध इलाहाबाद भाषण में सांप्रदायिक तनाव के समाधान के रूप में अलग मुस्लिम मातृभूमि का विचार दिया। उन्होंने पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को एक स्वायत्त मुस्लिम राज्य के रूप में संगठित करने की पैरवी की थी। भले ही 1940 में औपचारिक लाहौर प्रस्ताव आया, लेकिन पाकिस्तान आंदोलन की वैचारिक नींव इकबाल के 1930 के भाषण को ही माना जाता है। पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल बाद में चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने पत्र में पहली बार किया था, लेकिन इस अलगाववादी राष्ट्र की परिकल्पना इकबाल की थी। लाहौर प्रस्ताव (1940), जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया, मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को पारित किया गया था, जो अंततः देश विभाजन का आधार बना।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव वाराणसी में आज एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन में होंगे शामिल

● दोनों राज्यों की साझेदारी से बनेगा नया आर्थिक परिदृश्य ● काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे अध्ययन भ्रमण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वाराणसी में आयोजित 'एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026' में मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, पारंपरिक शिल्प, ओडीओपी और जीआई टैग उत्पादों, कृषि एवं खाद्य उत्पादों, निवेश अवसरों और पर्यटन संभावनाओं को एक साझा मंच पर प्रस्तुत करेंगे। इस सम्मेलन में दोनों राज्यों की प्रमुख ताकतें एक साथ सामने आएंगी और उत्पादन, बाजार तथा पहचान से जुड़े विभिन्न आयामों पर केंद्रित संवाद स्थापित होगा। सम्मेलन में उद्योग, शिल्प, निवेश और पर्यटन से जुड़े हितधारक एकत्रित होंगे, जहां व्यावहारिक सहयोग, बाजार विस्तार और साझा पहल पर चर्चा का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देगा।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण- मुख्यमंत्री डॉ. यादव की वाराणसी यात्रा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अध्ययन भ्रमण से होगी, जहां तीर्थ क्षेत्र में विकसित क्राउड फ्लो मैनेजमेंट, अधोसंरचना लेआउट और तीर्थयात्री प्रबंधन की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जाएगा। यह अनुभव धार्मिक पर्यटन स्थलों के सुव्यवस्थित विकास और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली को समझने का आधार बनेगा।

इसके बाद एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन स्थल पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा, जिसमें मध्यप्रदेश के ओडीओपी उत्पाद, जीआई टैग हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, औद्योगिक क्षमताएं और पर्यटन संभावनाएं प्रदर्शित होंगी। यह प्रदर्शनी राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता को एक ही मंच पर प्रस्तुत करते हुए निवेशकों और प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का कार्य करेगी।

सम्मेलन के मुख्य सत्र में निवेश, औद्योगिक सहयोग और ओडीओपी आधारित अर्थव्यवस्था पर केंद्रित चर्चा होगी, जहां मध्यप्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों, अधोसंरचना और प्रोत्साहन तंत्र को प्रस्तुत किया जाएगा। इसी सत्र में मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच एमओयू हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, हस्तशिल्प संवर्धन और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को औपचारिक रूप दिया जाएगा। ओडीओपी उत्पादों का आदान-प्रदान स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आएगा। दोपहर पश्चात नेटवर्किंग सत्र में उद्योग जगत, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के बीच संवाद स्थापित होगा, जिससे संभावित निवेश और साझेदारियों को गति मिलेगी और यह सम्मेलन वास्तविक व्यावसायिक अवसरों से जुड़ता हुआ दिखाई देगा।

समानांतर सत्रों में सहयोग के व्यावहारिक आयामों को विस्तार दिया जाएगा। संयुक्त शिल्प कार्यशाला में मध्यप्रदेश के चंदेरी और महेश्वरी शिल्पकार उत्तरप्रदेश के बनारसी सिल्क कारीगरों के साथ साझा ब्रांडिंग, बाजार विस्तार और 'गंगा-नर्मदा क्राफ्ट कॉरिडोर' की अवधारणा पर कार्य करेंगे, जिससे पारंपरिक शिल्प को नए बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में ठोस पहल होगी।

टूरिज्म राउंड टेबल मीटिंग

टूरिज्म राउंड टेबल में वाराणसी, उज्जैन और चित्रकूट को जोड़ते हुए एक संयुक्त धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस प्रक्रिया में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन सहित प्रमुख हितधारकों की सहभागिता से पर्यटन को संगठित और विस्तारित स्वरूप देने की दिशा में सहमति बनेगी।

विक्रमोत्सव महानाट्य मंचन के स्थल का अवलोकन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव वाराणसी के बी.एल.डब्ल्यू मैदान में 3 से 5 अप्रैल तक होने वाले महानाट्य विक्रमोत्सव के कार्यक्रम स्थल का मुआयना भी करेंगे।

काटजू अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा

डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने खुद को कमरों में किया बंद, लेबर पेन के दौरान बिगड़ी स्थिति

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में रविवार रात नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। गुस्साए परिजन अस्पताल परिसर में विरोध करने लगे। महिला डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ खुद को कमरों में बंद कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात संभाले। इस पूरे मामले में परिजन जहां डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इसे जटिल चिकित्सीय स्थिति बताते हुए अपनी सफाई दी है।

पहला बच्चा था, अचानक बिगड़ी हालत- परिजनों के अनुसार, संजना रैकवार को 9 माह की गर्भावस्था में शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया था। यह उनका पहला बच्चा था। रविवार शाम करीब 5 बजे उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई और लेबर रूम में सामान्य डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू हुई।

परिजन बताते हैं कि बच्चा आधा बाहर आ चुका था, लेकिन अचानक स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने प्रसूता को ऑपरेशन थियेटर में शिफ्ट कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें बताया गया कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। यह सुनते ही परिजन आक्रोशित हो गए।

परिजनों का आरोप- लापरवाही से गई जान- परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब प्रसव सामान्य हो रहा था, तो अंतिम समय में ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रसव के दौरान अस्पताल में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ मौजूद नहीं था, जिसके कारण ऑपरेशन में देरी हुई।

गोहत्या केस में खुलासे के बाद कांग्रेस हमलावर

विधायक मसूद बोले- उपद्रवियों पर हो सख्ती, आतिफ ने एनएसए नहीं लगाने पर उठाए सवाल

भोपाल (नप्र)। तलैया थाना क्षेत्र में काली मंदिर के पास मृत बछड़ा फेंकने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर उत्तर विधानसभा के विधायक आतिफ अकील ने पुलिस की मंशा और कार्रवाई में समानता पर सवाल उठाए हैं, वहीं मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर उपद्रव करने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफीज ने भी इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद शहर में आक्रोश का माहौल बना था और हिंदू संगठनों ने तलैया थाने का घेराव कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

उपद्रव करने वालों पर हो कार्रवाई- मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने दो अहम मुद्दों पर ध्यान दिलाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि दूसरी बार भी सच्चाई सामने लाई गई और

भोपाल की जनता हिंदू और मुस्लिम दोनों ने संयम और समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बार-बार शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही चेहरे हैं जो अलग-अलग जगहों पर उपद्रव करते नजर आते हैं। अब समय आ गया है कि इन पर सख्त कार्रवाई हो।

मसूद ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे तत्वों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे आंदोलन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भोपाल को नफरत के माहौल में नहीं जाने दिया जाएगा और शांति बनाए रखना प्राथमिकता है।

कार्रवाई में बराबरी क्यों नहीं?- विधायक आतिफ अकील ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, इसके लिए वे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने पूछा कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जबकि कई मामलों में दूसरे पक्ष पर तुरंत एनएसए लगा दिया जाता है, यहां ऐसा नहीं हुआ। कानून में मजहब का कोई एंगल नहीं होना चाहिए, कार्रवाई में बराबरी जरूरी है। विधायक ने यह भी कहा कि शहर में कुछ लोग भीड़ इकट्ठा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ अपेक्षित सख्ती नहीं दिखाई देती। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री से मांग की कि शहर की फिजा खराब करने वालों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई हो। गौरतलब है कि इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने तलैया थाने का घेराव कर विरोध जताया था और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने पांच दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया।

प्रदेश में अधिक से अधिक हों जल संवर्धन और जल संरक्षण के कार्य : जल संसाधन मंत्री सिलावट

जल गंगा संवर्धन अभियान संबंधी ली बैठक

भोपाल (नप्र)। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारी समाज के सभी वर्गों एवं आमजन के सहयोग से अपने-अपने क्षेत्र में वृहत रूप से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य कराएं और इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाएं। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान गत 19 मार्च से चलाया जा रहा है जो तीन माह तक चलेगा।

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में जल गंगा संवर्धन अभियान संबंधी बैठक लेकर अभियान के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा, अधीक्षण यंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्रीमती हर्षा जैनवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत आगामी दिनों में कराए जाने वाले कार्यों की कछारवार विस्तृत रूप रेखा तैयार कर आगामी 3 दिवस में प्रस्तुत की जाए। अभियान के सम्बन्ध में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में बताया गया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य रूप से जल संग्रहण स्त्रोतों के रख-रखाव एवं मरम्मत के अनुरूप अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना, निर्मित तालाब की पाल पर मिट्टी के कटाव अथवा अतिवर्षा से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पुनः निर्माण किये जाने, तालाबों की पिचिंग, बोल्डर टो तथा घाट आदि के मरम्मत का कार्य, जल संरचनाओं के किनारों पर अतिक्रमण को रोकना, संपूर्ण नहर प्रणाली में घास, झाड़ी, छोटे पेड़ पौधे आदि की सफाई का कार्य एवं वृक्षारोपण, शहरी आबादी क्षेत्रों में प्रमुख नहरों का चिन्हाकंन व सीमांकन का कार्य, स्टाप डेम बैराज-वीयर के गेट इत्यादि की मरम्मत, बांध के फ्लस बार स्लूज बेल की मरम्मत तथा सफाई का कार्य, केचमेंट एरिया में अवरोध का चिन्हांकन कर उसे हटाना तथा अन्य आवश्यक तकनीकी कार्य आदि कराए जा रहे हैं।

संपादकीय

नियुक्तियों में इतनी देरी क्यों?

मध्यप्रदेश में मोहन यादव सरकार ने अंततः प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैनों (मनोनीत पार्षद) की नियुक्ति कर दी है। ऐसी कुल 700 नियुक्तियां होनी है। लेकिन सवाल यह है कि एल्डरमैन जैसे जनसेवा के पद पर तैनाती में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि जो लोग इन पदों पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें काम करने का समय डेढ़ साल से भी कम मिलेगा। वैसे तो नियमानुसार एल्डरमैन का कार्यकाल वर्तमान परिषद के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन इस मामले में सरकार क्या करेगी, यह बाद में पता चलेगा। गौरतलब है कि एल्डरमैनों को जनता सीधे नहीं चुनती, बल्कि सरकार या संबंधित प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह नगर निकाय की बैठकों में शामिल होकर महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी राय देते हैं। साथ ही शहर के विकास, योजनाओं और परियोजनाओं पर सुझाव देते हैं और बैठक में शहर से जुड़े जरूरी मुद्दों को बैठक में उठाते हैं। इसके अलावा अपने अनुभव के आधार पर प्रशासन को बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति का मुख्य आधार प्रशासनिक अनुभव और नगर पालिका अधिनियम की जानकारी होता है। संगठन की सिफारिश पर नियुक्त होने वाले एल्डरमैन परिषद की बैठकों और चर्चाओं में तो सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, लेकिन इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता। बहरहाल राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित एल्डरमैनों की जो नियुक्तियां की हैं, उनमें 123 नगर परिषदों में 4-4, 46 नगर पालिकाओं में 6-6 मनोनीत पार्षद बनाए हैं। नगर निगमों में नियुक्तियां बाद में होंगी। सागर छोड़कर शेष बुंदेलखंड और चंबल के निकायों में सहमति न बन पाने के कारण फिलहाल लिस्ट होल्ड रखी गई है। एल्डरमैन के नामों की घोषणा नगरीय निकाय में सबसे शुरुआती इकाई यानी नगर परिषद से की गई है। राज्य में वर्तमान नगरीय निकायों का कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है। यानी एल्डरमैनों के पास काम करने के लिए डेढ़ साल से भी कम का वक्त है। इसलिए यह मानना गलत नहीं होगा कि इन नियुक्तियों के पीछे भाजपा और सरकार का असल मकसद प्रदेश में 2028 में होने वाले चुनाव के पूर्व नगरीय निकायों के सेमीफाइनल में अपनी स्थिति मजूबत करना है। इन नियुक्तियों केब बहाने अपने कार्यकर्ताओं को मैदानी स्तर पर एक्टिव करना चाहती है, इसलिए कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन का झुनझुना पकड़ा दिया गया है। बताया जाता है किन नियुक्ति के फॉर्मूले के तहत उन पुराने और अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें नगर प्रशासन का गहरा ज्ञान है। साथ ही कार्यकर्ताओं को 'कुछ न मिलने' की नाराजगी दूर करना भी है। सरकार चाहती तो यह नियुक्तियां दो साल पहले भी कर सकती थी। लेकिन आपसी खींचतान के चलते शायद यह संभव नहीं हुआ। ऐसे में एल्डरमैन की नियुक्ति कर चुनाव से पहले जिला स्तर के उन सक्रिय नेताओं को एडजेस्ट किया गया है, जो लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी ने अनुभवी एल्डरमैन के जरिए परिषदों के कामकाज और विकास कार्यों की निगरानी को मजबूत करने की कोशिश भी की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में नव-नियुक्त एल्डरमैनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आप सभी को शहर के समग्र विकास, सुशासन और जन-भागीदारी को बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। मुझे विश्वास है कि विकसित मध्य प्रदेश-विकसित भारत के संकल्प के साथ आप सभी अपनी ऊर्जा, अनुभव और समर्पण से अपने-अपने नगरों में प्रगति के नए आयाम जोड़ेंगे। नए एल्डरमैन सरकार की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं, यह तो अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव नतीजों से तय होगा।

युद्ध के बीच ईरान पर भारत का रुख सही

नजरिया

अवधेश कुमार
लेखक दिल्ली निवासी पत्रकार हैं।

अमेरिकी इजरायली संयुक्त हमले और उसके विरुद्ध ईरान की सैन्य प्रतिक्रियाओं पर देश के अंदर विरोध के परिदृश्य चिंताजनक आवश्यक हैं, पर आश्चर्य का विषय नहीं। भारत में अब ऐसी स्थिति नहीं जहां किसी मुद्दे पर देश की एकता दिखाई दे सके। संसद सत्र आरंभ होने के साथ सदन के अंदर और बाहर विरोध, नारेबाजी, बहिर्गमन, आरोप - प्रत्यारोप आदि की पृष्ठभूमि पहले से बनी हुई है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों से लेकर संसद के विरोध में सुसंगति है। कांग्रेस के साथ अधिकतर विपक्षी पार्टियों और नेताओं ने सरकार पर अमेरिकी दबाव के समक्ष घुटने टेकने और भारत की परंपरागत विदेश नीति को बदलने का आरोप लगाया है। बड़े-बड़े नेता बोल रहे हैं है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति को डोनाल्ड ट्रंप के हाथों गिरवी रख दिया है। मूल स्वर यह है कि भारत को ईरान के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था जबकि वह तटस्थता प्रदर्शित करते हुए भी अमेरिका और इजरायल के साथ खड़ा दिख रहा है। सोनिया गांधी ने लेख लिखा जिसमें कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर केंद्र सरकार का यह मौन तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस तरह के वक्तव्यों की सूची बड़ी होती जा रही है। तो क्या युद्ध में भारत की भूमिका वाकई गलत है?

पहले कुछ तथ्य देखें। ऑर्गेनाइजेशन औफ इस्लामी कॉन्फ्रेंस ओआईसी में 56 देश है। कोई भी देश ईरान के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है। छोटी-छोटी बातों पर बैठक बुलाने वाला ओआईसी चुप है। खाड़ी सहयोग परिषद की कोई टिप्पणी नहीं है। ईरान के 13 पड़ोसी मुस्लिम देश भी उसके साथ नहीं है। इसके कुछ तो कारण हैं। थोड़ी गहराई से देखें तो ईरान पर हमले के संदर्भ में इस तरह का आंतरिक विरोध दो ही देश में दिख रहा है, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान में हिंसा करते लोग लगातार मारे जा रहे हैं। अनेक शहरों में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। भारत में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई तो इसका कारण दोनों देशों के संस्कार और चरित्र के बीच का मौलिक अंतर ही है। इसका उल्लेख इसलिए जरूरी है ताकि समझें कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हम विदेश नीति पर आंतरिक व्यवहार के मामले में पाकिस्तान के समक्ष स्वयं को देखना और दिखाना चाहते है? किसी को अतिश्योक्ति लगे लेकिन सच्चाई यही है। हमले के जवाब में इजराल को निशाना बनाने के साथ ईरान ने सउदी अरब, क़तर, अमीरात, ओमान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, साइप्रस पर मिसाइलों से चुन-चुन कर हमले किये हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सउदी अरामको तेल रिफाइनरी ईरान हमले के बाद बंद हो गई थी। रूस की सलाह पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कुछ पड़ोसी देशों से क्षमा मांगी और घोषणा किया कि हमले नहीं करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। ईरान के मिसाइल लगातार अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने के नाम पर इन देशों पर बरस रहे। कोई दिन नहीं जब इन देशों से बयां नहीं आते कि हमने ईरान के इतने ड्रोन नष्ट किया या मिसाइल इंटरसेप्ट किया।

ईरान के लिए आसमान सिर पर उठाने लेने वाले क्या चाहते हैं कि भारत अमेरिका और इजरायल के विरुद्ध मोर्चा ले? चीन और रूस ने इस हमले का विरोध अवश्य किया। क्या इससे आगे वे कुछ करने को तैयार हैं? अमेरिका द्वारा हिन्द महासागर में ईरान के युद्धपोत को नष्ट करने को भारत के लिए शर्मशार करने वाली घटना बताने वाले जानते हैं कि वे सच नहीं बोल रहे। पोत भारत के आगे श्रीलंका की समुद्री सीमाओं से भी बाहर चला गया था। युद्ध की स्थिति में ईरान का युद्धपोत -विमान कहीं भी होगा निशान बनेगा। ईरान भी अपनी शक्ति भर यही कर रहा है। हम न भूले कि ईरान का एक पोत अभी कोच्चि बंदरगाह पर सुरक्षित है और उसके सारे क्रू भी। क्या अमेरिका ने भारत से पूछा कि युद्ध के बीच आपने ईरान के युद्धपोत और उसके क्रू को क्यों सुरक्षित रखा हुआ है? इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है। ध्यान रखिए आज ईरान के लिए आवाज उठाने वालों ने 7 अक्टूबर, 2023 को उत्सव मनाते इजरायलियों पर हमास द्वारा बर्बरतापूर्ण हमले, कत्लेआम और बंधक बनाए जाने पर निंदा का एक शब्द न बोला और केवल हमास के लिए खड़े दिखे। यह कैसी सिद्धांतवादिता है? ऐसा करते समय नहीं सोचा कि इसराइल पर क्या गुजरेगी? या स्टैंड भारत के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध था।

ईरान के साथ भारत के संबंधों को न मित्रतापूर्ण कह सकते हैं न शत्रुतापूर्ण। मान लीजिए कि ईरान के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे थे। विदेश नीति और रक्षा नीति वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होती हैं। क्या इजराइल से हमारे संबंध बुरे रहे हैं? ऐसा कौन कठिन अवसर है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर इजरायल ने साथ नहीं दिया है? 1962 से लेकर हर युद्ध में इजराइल भारत के साथ रहा है। 1962 में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर उसने बिना चिन्ह लगाए हथियारों का खेप भेजा। अमेरिका से व्यापार को लेकर ट्रंप की नीतियों में अवश्य दुराव पैदा हुआ किंतु आज भी वह हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, सबसे अधिक लाभ देने वाला देश है तथा सामरिक सहयोग उस सीमा तक पहुंच गए हैं जहां हम एक दूसरे के रक्षा लॉजिस्टिक तक का उपयोग कर सकते हैं।

ईरान ने जितनी भारी मात्रा में मिसाइल इकट्ठे किए उसका कोई वाजिब कारण है? ईरान पहले से पूरे क्षेत्र में आक्रमण करता रहा है। 2019 में भी उसने सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। ओमान की खाड़ी में जहाजों को निशान बनाया। इराक में कुर्दों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। सीरिया और पाकिस्तान में उसकी मिसाइलें गिरीं। कहा गया कि वहां से हथियारबंद समूह ईरान विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। हिज्बुल्लाह, हुती, हमास जैसे आतंकवादी समूहों को पालने वाला देश शांतिवादी नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के एक भाग पर उसका कब्जा है तथा वहां के मुक्ति आंदोलन का वह भी पाकिस्तान की तरह क्रूरता से दमन कर रहा है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद उसका सबसे पहला युद्ध इराक से हुआ जो एक दशक चला। इजरायल को धरती पर नहीं रहने के अधिकार की घोषणा करने वाले तथा पड़ोसी देशों को हमेशा अपनी सैन्य ताकत से भयभीत रखने की नीति वाले ईरानी शासन का कौन साथ देगा? इजरायल ईरान का पड़ोसी भी नहीं है। इजरायल का अब पड़ोसी जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों के साथ कोई तनाव नहीं। हिज्बुल्लाह को छोड़ दें तो उसका लेबनान से तनाव खत्म हो सकता है।

भारत के संबंध अरब के सभी देशों से हैं और लगभग एक करोड़ भारतीय में सबसे कम ईरान में ही केवल दस हजार हैं। जरा सोचिए, ईरान के साथ खुलकर खड़ा होने का संदेश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात , बहरीन, ओमान, कुवैत आदि देशों में कैसा जाएगा? ओमान के साथ कुछ ही महीने पहले हमारा सामरिक साझेदारी समझौता हुआ है। न्यायपूर्ण व्यवहार तो यही है कि ईरान इजरायल का अस्तित्व स्वीकारे, पड़ोसी देश को अपने सैन्य ताकत का भय दिखाना बंद करे, आतंकवादी समूहों को समर्थन न दे तथा नाभिकीय हथियार बनाने की सोच का मान्य परित्याग करे। क्षेत्र के साथ-साथ यही भारत के भी हित में है। कांग्रेस भूल रही है कि 2006 में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय आणविक एजेंसी में लाए गए प्रस्ताव का तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने समर्थन किया था। भारत का इसी में राष्ट्रीय हित था। निश्चित रूप से इस युद्ध से हमारी समस्याएं बढ़ीं है खासकर पेट्रोलियम आपूर्ति के संदर्भ में और उसका असर दिख रहा है। किंतु इसका सामना संपूर्ण देश को मिलकर ही करना होगा। यह संकट अकेले भारत का नहीं संपूर्ण विश्व के लिए है। ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना तो मामले को और जटिल बनाएगा। भारत कभी युद्ध के साथ नहीं हो सकता किंतु जिन घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ईरान 1979 के इस्लामी क्रांति के बाद छद्म युद्ध लगातार लड़ रहा है। विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर निर्धारित होती है और भारत इस मामले पर सही दिशा में है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने ईरान दूतावास जाकर अयातुल्लाह अल खामेनेई की मृत्यु पर शोक संदेश लिखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 मार्च को संसद में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने 20 फरवरी को बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान का बयान दिया था। उनके वक्तव्य का मुख्य सार यही था कि हमारी चिंता खाड़ी में रह रहे एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा है और फंसे लोगों को निकालने के इंतजाम किए जा चुके हैं। उन्होंने अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ ईरान के विदेश मंत्री से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकतर अरब देशों के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। वस्तुत भारत का रुख शत प्रतिशत राष्ट्रीय हित के अनुकूल है और युद्ध का अंत जैसे भी हो हमारे संबंध पूरे क्षेत्र में सामान्य रहेंगे।

डिजिटल लेनदेन में न्याय की नई लकीर

डिजिटल इंडिया

डॉ. राजेश कुमार गुप्ता
(दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता)

रेजरपे जैसे पेमेंट एग्रीगेटर एक 'पाइपलाइन' की तरह हैं। यदि उस पाइप लाइन से गंदा पानी (अवैध धन) गुजरता है, तो इसके लिए पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी तब तक दोषी नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उसने जानबूझकर गंदा पानी प्रवाहित करने के लिए पाइपलाइन खोली थी। कानून का एक प्राचीन और सर्वमान्य सिद्धांत स्पष्ट करता है कि केवल कोई कृत्य किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाता, जब तक कि उसके पीछे कोई आपराधिक मंशा न हो।

21वीं सदी का भारत एक डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। आज एक रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक 'यूपीआई' और 'डिजिटल वॉलेट' हमारी जीवन रेखा बन चुके हैं। जब हम 'डिजिटल इंडिया' और 'कैशलेस इकोनॉमी' की सफलता की बात करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान केवल लेनदेन की गति और सुविधा पर होता है। लेकिन इस चमक-धमक वाले डिजिटल बुनियादी ढांचे के पीछे एक जटिल कानूनी मशीनरी काम करती है, जिसे 'अदृश्य न्यायशास्त्र' कहा जा सकता है। 2 मार्च 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेजरपे बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में दिया गया निर्णय इसी अदृश्य ढांचे को मजबूती प्रदान करने वाला एक युगांतरकारी फैसला है। यह निर्णय केवल एक कॉर्पोरेट राहत नहीं, बल्कि यह भारत के उभरते हुए फिनटेक क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा कवच है। न्यायालय ने इस निर्णय के माध्यम से मध्यस्थ और वास्तविक अपराधी के बीच की उस धुंधली रेखा को स्पष्ट कर दिया, जिसे अक्सर जांच एजेंसियां अपने विवेकाधीन शक्तियों के अति-उत्साह में मिटा देती थीं। इस विवाद की पृष्ठभूमि में अवैध चीनी लोन ऐप्स और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों द्वारा भारतीय नागरिकों को छोटे ऋण के जाल में फंसाकर की गई जबरन वसूली और डेटा चोरी शामिल है। इन अपराधियों ने अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए रेजरपे और कैशफ्री जैसे वैध 'पेमेंट गेटवे' का उपयोग एक 'कवर' के रूप में किया। जब प्रवर्तन निदेशालय ने इन घोटालों की जांच शुरू की, तो धन शोधन निवारण अधिनियम की व्यापक व्याख्या के कारण ये निर्दोष सेवा प्रदाता भी कानूनी जांच के दायरे में आ गए।

न्यायालय ने माना कि रेजरपे जैसे पेमेंट एग्रीगेटर एक 'पाइपलाइन' की तरह हैं। यदि उस पाइप लाइन से गंदा पानी (अवैध धन) गुजरता है, तो इसके लिए पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी तब तक दोषी नहीं है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उसने जानबूझकर गंदा पानी प्रवाहित करने के लिए पाइपलाइन खोली थी। कानून का एक प्राचीन और सर्वमान्य सिद्धांत स्पष्ट करता है कि केवल कोई कृत्य किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाता, जब तक कि उसके पीछे कोई आपराधिक मंशा न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में इसी 'मेन्स रिया' यानी 'आपराधिक मंशा' के महत्व को डिजिटल युग के संदर्भ में गहराई से रेखांकित किया है। आधुनिक पेमेंट गेटवे के कामकाज का विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने 'ऑटोमेशन बनाम मंशा' के तर्क को मजबूती दी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म प्रतिदिन करोड़ों लेनदेन को स्वचालित एल्गोरिदम के माध्यम से संसाधित करता है। चूँकि इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, इसलिए यदि कोई सॉफ्टवेयर कोड किसी लेनदेन को तकनीकी रूप से 'सफल' दिखाता है, तो उसमें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत 'साजिश' या आपराधिक इरादा ढूंढना तार्किक नहीं है।

इसी क्रम में न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में सहायता करना या संलिप्त होना जैसे शब्दों का अर्थ केवल जानबूझकर की गई सहायता से ही लिया जाना चाहिए। न्यायालय के अनुसार, किसी अनजाने में प्रदान की गई तकनीकी सेवा या बुनियादी ढांचे के उपयोग को लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह स्पष्टीकरण उन सेवा प्रदाताओं के लिए एक बड़ा कानूनी रक्षा कवच है जो केवल एक माध्यम या पाइपलाइन के रूप में कार्य करते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य अवैध धन को वैध बनाना नहीं, बल्कि तकनीकी सुगमता प्रदान करना होता है। न्यायालय द्वारा स्थापित यह अंतर इस पूरे निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत हिस्सा माना जा सकता है, जहाँ 'नियामक चूक' और 'आपराधिक अपराध' के बीच एक अत्यंत बारीक लेकिन स्पष्ट विभाजन रेखा खींची गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कंपनी केवाईसी नियमों का पालन करने में कोताही बरतती है या भारतीय रिजर्व बैंक को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट समय पर नहीं भेजती, तो इसे एक 'प्रशासनिक विफलता' या नियामक चूक माना जाना चाहिए, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास संबंधित कंपनी पर भारी जुर्माना लगाने या उसका लाइसेंस रद्द करने जैसे पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं। इसे सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का दोष सिद्ध करने के लिए व्यक्ति या संस्था की सक्रिय और सचेत भागीदारी अनिवार्य है, न कि केवल तकनीकी संपर्क। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों को आगाह किया है कि वे सिविल या प्रशासनिक चूकों (जैसे केवाईसी में देरी) को आपराधिक अपराध का रंग देने से बचें। चूंकि, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत मिलना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसका प्रयोग केवल वास्तविक अपराधियों और प्रत्यक्ष लाभार्थियों के विरुद्ध ही होना चाहिए। यह निर्णय उन उद्यमियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिनसे अनजाने में प्रक्रियात्मक चूक हुई हो, और उन्हें जान-बूझकर वित्तीय प्रणाली को दूषित करने वाले अपराधियों से अलग करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने रेजरपे मामले में अपने विवेक का उपयोग करते हुए पूर्व के महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांतों को आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुकूल ढाला है। न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी (2022) के धन शोधन निवारण अधिनियम संबंधी कठोर सिद्धांतों को फिनटेक की विशिष्ट कार्यप्रणाली से जोड़कर 'तकनीकी-अनुकूल' बनाया है, वहीं श्रेया सिंघल (2015) के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले तर्क को यहाँ अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत 'व्यापार की स्वतंत्रता' के संरक्षण के रूप में विस्तार दिया है। साथ ही, गूगल इंडिया बनाम विशाखा इंडस्ट्रीज में प्रतिपादित 'मध्यस्थ देयता' के सिद्धांतों को पुनः परिभाषित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को उनके उपयोगकर्ताओं के हर अवैध कृत्य के लिए स्वतः जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिससे तकनीकी क्षेत्र में अनावश्यक कानूनी भय को कम करने का प्रयास किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' और भारत के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए संजीवनी समान है। विशेषकर फिनटेक क्षेत्र में, जहां नवाचार और बैंकिंग का संगम है, वहाँ 'नियामक आतंकवाद' और बिना ठोस साक्ष्यों के दंडात्मक कार्रवाई का भय अक्सर पूंजी के पलायन का कारण बनता रहा है। न्यायपालिका का यह रुख न केवल स्टार्टअप संस्थापकों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों में यह विश्वास भी जगाता है कि भारतीय कानूनी ढांचा आधुनिक तकनीक और व्यापारिक बारीकियों के प्रति संवेदनशील है। यह फैसला वैश्विक बाजार में भारत की विश्वसनीयता बढ़ाने और नवाचार को निर्बाध गति देने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

यह अंश डिजिटल न्यायशास्त्र के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण 'नजीर' प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट करता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न या सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप को तीसरे पक्ष द्वारा की गई अवैध गतिविधियों के लिए केवल तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जब उनकी 'सक्रिय मिलीभगत' या 'जानकारी' सिद्ध हो। 'ज्ञान के स्तर' का यह सिद्धांत न केवल वर्तमान डिजिटल माध्यमों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, बल्कि भविष्य में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य तकनीकी नवाचारों के नियमन के लिए भी एक आधार तैयार करता है, ताकि संस्थाएं अपने उपयोगकर्ताओं के अनपेक्षित कृत्यों के लिए कानूनी रूप से प्रताड़ित न हों। रेजरपे बनाम ईडी मामले का यह निर्णय तकनीक और कानून के बीच एक प्रगतिशील संतुलन स्थापित करता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल युग में कानून की व्याख्या को सटीक और व्यावहारिक होना अनिवार्य है, ताकि निर्दोष तकनीक प्रदाताओं को केवल अपराधी के संपर्क में आने मात्र से दंडित न किया जाए। यह निर्णय 'अपराध' और 'औजार' के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि तकनीक निर्माता तब तक उत्तरदायी नहीं है जब तक उसकी सक्रिय आपराधिक मंशा न हो। अंततः, न्याय की यह नई दिशा भारत को एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की ओर एक साहसिक कदम है।

क्या विरोध ही आजादी है?

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया
लेखक स्तंभकार हैं।

आज के समय में 'आज़ादी' शब्द का अर्थ धीरे-धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर किशोरावस्था में पहुँचते ही कई युवा हर बात का विरोध करना ही अपनी स्वतंत्रता समझने लगते हैं। चाहे बात घर के नियमों की हो, समाज की परंपराओं की हो या फिर बड़ों की सलाह की विरोध मानो एक आदत बनती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हर चीज़ का विरोध करना ही आज़ादी है?

किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपनी पहचान खोजने की कोशिश करता है। इस दौरान उनके मन में नए विचार, जिज्ञासाएँ और अपने फैसले खुद लेने की इच्छा जागृत होती है। यह स्वाभाविक भी है। परंतु जब यही भावना अति में बदल जाती है, तो वह जिद और अहंकार का रूप ले लेती है। हर बात में 'ना' कहना, बिना समझे विरोध करना, और सही-गलत का भेद किए बिना अपने विचारों को ही अंतिम मान लेना—यह प्रवृत्ति कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व को नुकसान पहुँचाती है।

आज़ादी का वास्तविक अर्थ जिम्मेदारी के साथ जुड़ा होता है। यदि हम केवल विरोध को ही स्वतंत्रता मान लें, तो यह हमें सही दिशा से भटका सकता है। कई बार माता-पिता या शिक्षक जो सलाह देते हैं, वह हमारे भले के लिए होती है। लेकिन आज की पीढ़ी इसे अपनी स्वतंत्रता पर हमला समझ बैठती है। परिणामस्वरूप, वे न केवल अपनों से दूर होते जाते हैं, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी कठिनाइयाँ खड़ी कर लेते हैं। यह रवैया उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी हानिकारक हो सकता है। लगातार विरोध करने की आदत व्यक्ति को अस्थिर, असंतुलित और नकारात्मक सोच वाला बना सकती है। ऐसे में वह सही निर्णय लेने में भी असमर्थ हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आज की युवा पीढ़ी 'आज़ादी' के सही अर्थ को समझे। स्वतंत्रता का मतलब केवल अपनी बात मनवाना नहीं, बल्कि दूसरों की बात सुनना, समझना और सही निर्णय लेना भी है। विचारों में भिन्नता होना गलत नहीं है, परंतु हर बात का विरोध करना समझदारी नहीं कहलाता।

अंततः यही कहा जा सकता है कि सच्ची आज़ादी वही है, जिसमें समझ, संतुलन और जिम्मेदारी हो। यदि आज की पीढ़ी इस बात को समझ ले, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बन सकती है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

फोकटिया संघ की दैनिक बैठक

व्यंग्य

डॉ. महेन्द्र अग्रवाल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

कल देर रात ग्यारह बजकर तैंतीस मिनिट पर फोकटिया संघ की दैनिक बैठक में बात चल निकली कि कवि कौन होते हैं ? वहां उपस्थित सर्वकालिक ठुलुओं में सभी की इस बिंदु पर अलग-अलग राय थी, जोकि स्वाभाविक है पर इस बात पर सभी एकमत थे कि असली कवि वही होते हैं जो न कभी खुद सुखी रहते हैं और न कभी दूसरों को सुखी रहने देते हैं । इस पर सर्वमान्य राय कायम होने के बाद उस दिन की सभा की अध्यक्षता कर रहे विशेष चिंतक ने अपने स्पेशल कमेंट में कहा कि जो अपने मन की सुना दे पर दूसरे की कभी न सुने उसे ही सच्चा कवि कहते हैं।यह सुनते ही प्रतिक्रिया व्यक्त करने को आतुर अगले दिन के लिए नामित दक्षिणपंथी अध्यक्ष ने कहा कि भाई कवियों के पीछे ही क्यों पड़े हो ,इसमें शायरों को भी जोड़ लो। उर्दू कौन सी तुम्हारी मादरी ज़बान है ? यह सुन गत दिवस के निवर्तमान अध्यक्ष तुरंत बोल पड़े -यार अदबी चर्चा में भी तुम पॉलिटिक्स बीच में ले आते हो ।कुछ बातें राजनीतिज्ञों को रहने दो,शायरों को जोड़ना है तो जोड़ लो। इससे आगे क्यों बढ़ते हो ?

अब भीड़ में सभी बुद्धिजीवी होने का भ्रम पाले थे सो चुप कौन रहे? पहचान का संकट सम्मुख था इसलिए सबका बोलना ज़रूरी था। एक ने कहा-पहले तो केवल मंच पर ही मारामारी थी वह भी केवल माइक को लेकर,लेकिन अब तो सोशल मीडिया पर गदर कट रहा है । दूसरा बोला जिसे देखो वही कवि-शायर है।या तो आंखों में कविता डाल रहा है या सीधे-सीधे अपनी आवाजकानों में पेल रहा है । तीसरे ने कहा-बाढ़ सी आ गई है जैसे बाढ़ का पानी उतरने के बाद इधर-उधर से कचरा इकट्ठा हो जाता है वही हालत सोशल मीडिया की हो गई। देश भर के कवि शायर यहीं मर रहे हैं।

चौथे ने अपना ज्ञान बघारा-सोशल मीडिया तो संचार, मनोरंजन, शिक्षा,सूचना, मार्केटिंग,ब्रांडिंग आदि के लिए इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है,इसमें भी दूसरों का दिमाग खराब करना? छठे ने जानकारी में संशोधनकिया-फेसबुक तो मार्क जकरबर्ग और उनके मित्रों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को आपस में जोड़ने, संवाद कायम करने और अपनी-अपनी जानकारी के आदान-प्रदान के लिए बनाई थी ताकि सभी एक ही नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़ें, बाद में यही पूरी दुनिया के लिए सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया।सातवे ने उच्छ्वास किया- तब भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जम्बू द्वीप भरत मंडल में यह प्लेटफॉर्म हाथ लगते ही कवि शायरों की उचट के लग जायेगी।इसका मूल उद्देश्य तो पुराने लोगों से संबंध बनाने और नए लोगों को जोड़ने का था। आठवा बड़ी देर से रुका था,फट पड़ा-हमारे यहां आपदा में अवसर ढूंढ़ते हैं और सुविधा में सत्यानाश की संभावनाएं। सो इसका भी दुरुपयोग होने लगा है। साधन मिलते ही सब साध्य तलाशने लगे। इसे अपनी भड़ास का माध्यम बना डाला। अब तो हालात ये है कि फेसबुक खोलते ही कविता और शायरी धुंध की तरह आंखों के आगे छाने लगती है। कुछ सुनाई देता है तो मंच के अभ्यासी लोगों का रुदन या विज्ञप्तिनुमा काव्य पाठ। उनकी चार पंक्तियां भी लगातार चालीस बार चली आती हैं। फेसबुक पर आधी से अधिक जगह तो इन्हीं कवि शायरों ने घेर रखी है । बाकी में चालीस फीसदी पर राजनीतिक पार्टियों के आई. टी.सेल कब्जा किये बैठे हैं । अब बचा क्या ? उसमें भी धर्म का प्रचार प्रसार,मंदिरों के विज्ञापन आने लगे। ऑनलाइन भेंट दक्षिणा से पूजा अर्चना की ऑनलाइन व्यवस्था होने लगी है । गुरु से लेकर मंगल शनि के दोष निवारण का काम भी चल रहा है। जिस मंदिर का प्रसाद चाहो ऑनलाइन पेमेंट करो और घर बैठे ले लो, जैसे कुछ दिन पहले सरकार ने डाक विभाग से गंगा जल के भिजवाने की व्यवस्था बनाई थी ।अब तो देव दर्शन हो, मंगला आरती हो या शयन आरती,सब कुछ ऑनलाइन है।सबके फेसबुक पेज बने हैं ।

अबकी वह बोला जो शायद सुरक्षित था और अभी तक बोलने से वंचित था। उसने शिकायती लहजे में कहा-पर ये सब उन्हें ही नसीब है जिन पर एन्डरोइड फोन है,वरना पुराने नोकिया वालों की भी कोई ज़िंदगी है ? यह तो खुद 'नो किया'बनकर रह गए हैं।

हमारी दुनिया

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

चिली : शुष्क मिर्च में डेजर्ट का आकर्षण

इटली का मानचित्र एक बूट की तरह दिखता है। ऑट्रेलिया का मानचित्र एक हाथी की तरह, फ्रांस का मानचित्र एक षट्भुज की तरह, श्रीलंका का मानचित्र आंसू की एक बूंद की तरह, जापान का मानचित्र एक ड्रैगन की तरह दिखता है। कोस्टारिका का मानचित्र एक पेंसिल की तरह दिखता है। क्यूबा का मानचित्र मगरमच्छ की तरह, आइसलैंड का मानचित्र एक बड़े पत्थर की तरह और ग्रीस का मानचित्र एक हाथ की तरह दिखाई देता है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित चिली भी अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति और बनावट में एक मिर्ची के रूप में दिखाई देता है। जो दुनिया का सबसे बड़े मिर्च उत्पादक देशों में से भी एक है। यह देश अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा देश है, जो 4,300 किलोमीटर से अधिक लंबा है, लेकिन इसकी औसत चौड़ाई केवल 180 किलोमीटर है।

विश्व मानचित्र को देखने पर रचनात्मक दृष्टि संपन्न लोगों ने उसमें पृथ्वी के समस्त भूभाग में फुटबॉल खेलती एक मासूम बिल्ली की आकृति की कल्पना की है। गौर से देखने पर यह दिखाई भी देता है। भारत के नक्शे में हम भारत माता को तिरंगा थामे खड़े अनुभव करते हैं। अनेक देश प्रदेशों ने अपने भूभाग में किसी न किसी चीज या प्रिय के प्रतीकात्मक आकार महसूस किया है।चिली देश के मानचित्र में मिर्च की कल्पना की गई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक देशों में से एक है। इसी तरह, अन्य देशों के मानचित्र में भी विभिन्न वस्तुओं, प्राणियों या प्रतीकों की कल्पना की गई है।

इटली का मानचित्र एक बूट की तरह दिखता है। ऑट्रेलिया का मानचित्र एक हाथी की तरह, फ्रांस का मानचित्र एक षट्भुज की तरह,श्रीलंका का मानचित्र आंसू की एक बूंद की तरह, जापान का मानचित्र एक ड्रैगन की तरह दिखता है। कोस्टारिका का मानचित्र एक पेंसिल की तरह दिखता है। क्यूबा का मानचित्र मगरमच्छ की तरह, आइसलैंड का मानचित्र एक बड़े पत्थर की तरह और ग्रीस का मानचित्र एक हाथ की तरह दिखाई देता है।

इसी तरह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित चिली भी अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति और बनावट में एक मिर्ची के रूप में दिखाई देता है। जो दुनिया का सबसे बड़े मिर्च उत्पादक देशों में से भी एक है। यह देश अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा देश है, जो 4,300 किलोमीटर से अधिक लंबा है, लेकिन इसकी औसत चौड़ाई केवल 180 किलोमीटर है।

एक बड़ी पतली मिर्च के आकार वाले देश चिली के नाम के पीछे कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानी यह है कि देश का नाम चिली शब्द से आया है, जो कि मैपुचे भाषा से लिया गया है। मैपुचे दक्षिणी चिली में रहने वाले स्वदेशी समुदाय हैं। एक सिद्धांत के अनुसार, चिली शब्द का अर्थ है 'जहां पृथ्वी समाप्त होती है' या 'पृथ्वी का अंत'। यह नाम संभवतः मैपुचे लोगों द्वारा दिया गया था, जो चिली को अपनी पृथ्वी की सीमा मानते थे। एक अन्य कहानी के अनुसार, चिली का नाम चिली पेप्पर से आया है, जो कि देश में पाया जाने वाला एक प्रकार की मिर्च है। स्पेनिश विजेताओं ने इस मिर्च को चिली कहा, और बाद में यह नाम पूरे देश के लिए उपयोग किया जाने लगा। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार, चिली का नाम इंका भाषा के शब्द चिली से आया है, जिसका अर्थ है ठंड या बर्फ। यह नाम संभवतः इंका साम्राज्य के दौरान दिया गया था, जब उन्होंने चिली को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था । वस्तुतः इन सब कहानियों से उसके अनोखे मिर्ची आकार के कारण ही मान्यता मिलती है।

चिली में तीन मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हैं, अटाकामा डेसर्ट (उत्तर), सेंट्रल वैली (मध्य), और पैटागोनिया (दक्षिण)। देश में कई सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप-प्रवण क्षेत्र हैं। चिली की राजधानी सैंटियागो है, जो सेंट्रल वैली में स्थित है। चिली एक उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था है, जो मुख्य रूप से तांबे के निर्यात पर निर्भर है। देश में लिथियम, सोना और अन्य खनिजों के भंडार भी हैं। चिली की अर्थव्यवस्था 2024 में 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। चिली की आबादी लगभग 18.66 मिलियन है, जिसमें से 88 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। यहां उच्च जीवन प्रत्याशा (80.3 वर्ष) और उच्च साक्षरता दर है। चिली में एक मजबूत मध्यम वर्ग है, लेकिन अभी भी आय असमानता एक समस्या है।

पर्यटनीय दृष्टि से चिली में कई प्राकृतिक आकर्षण हैं। अटाकामा डेसर्ट, पैटागोनिया, और ईस्टर द्वीप और कई राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र भी हैं जिनमें पर्यटक निरंतर आते रहते हैं। राजधानी सैंटियागो स्वयं एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आकर्षणों के लिए जाना जाता है ।

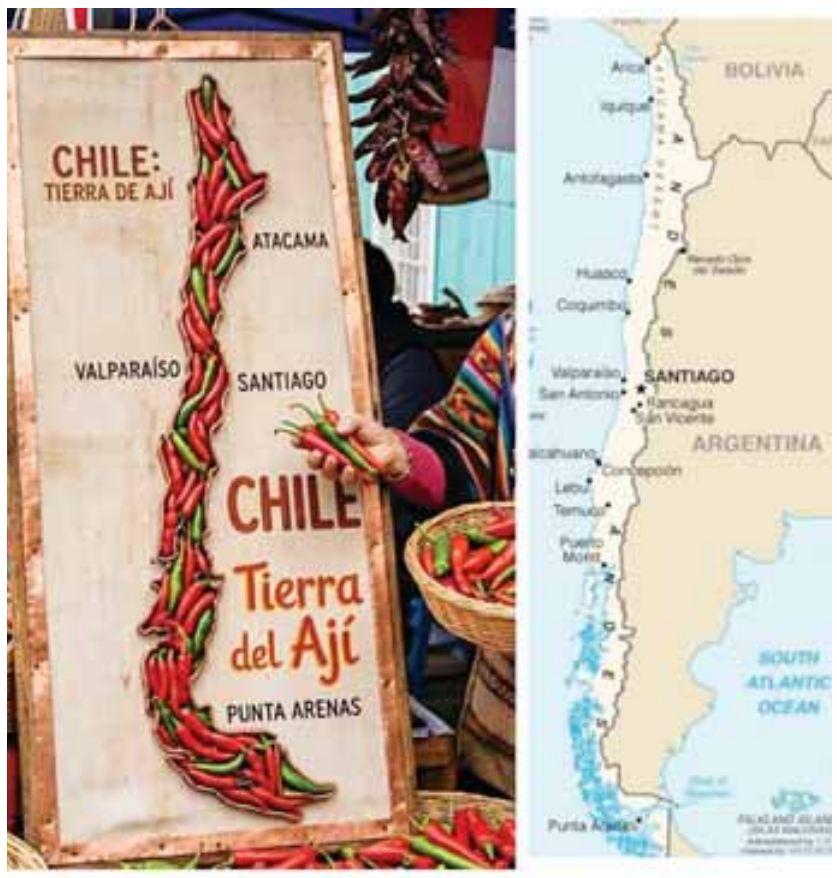

विश्व साइकिल यात्री साइकिल बाबा के डॉ राज और नोमेडिक टूर के तौरवशु के ट्रैवल वीडियोस के जरिए हमने चिली की आभासी यात्रा में यहां के प्रमुख स्थलों और विशेषताओं को देखने समझने की कोशिश की। खासतौर से चिली में स्थित अटाकामा रेगिस्तान के प्रमुख स्थल बहुत प्रभावित करते हैं।

दुनिया भर में फैले रेगिस्तान पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत हिस्सों में से हैं। ये केवल रेत के ढेर नहीं हैं, बल्कि अपनी भौगोलिक बनावट और जलवायु के कारण एक-दूसरे से काफी भिन्न हैं। उत्तरी अफ्रीका का सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, चीन और मंगोलिया में फैला गोबी रेगिस्तान बेहद ठंडा और ऊंचे पहाड़ों और बर्फीली सर्दियों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा और ठंडा ध्रुवीय रेगिस्तान अंटार्कटिक है जो दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। हमारे भारत और पाकिस्तान में स्थित थार मरुस्थल सबसे अधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान है।

चिली में स्थित अटाकामा रेगिस्तान को दुनिया का सबसे सूखा (Non-polar) स्थान माना जाता है। इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं इसे अन्य रेगिस्तानों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। अत्यधिक शुष्क इस रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में सैकड़ों सालों से एक बूंद बारिश भी नहीं हुई है। यहाँ की मिट्टी इतनी सूखी है कि इसकी तुलना मंगल ग्रह (Mars) की मिट्टी से की जाती है। यही कारण है कि नासा (NASA) यहाँ अपने मार्स रोवर का परीक्षण करता है।

यह एंडीज पर्वतमाला और चिली कोस्ट रेंज के बीच स्थित है। एंडीज पर्वत पूर्व से आने वाली नमी को रोक देते हैं (Rain Shadow Effect), जिससे यहाँ बारिश की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। बारिश न होने के बावजूद, समुद्र की ओर से आने वाला घना कोहरा (जिसे स्थानीय भाषा में 'कैमंचका' कहते हैं) यहाँ के जीवन का आधार है। यहाँ के लोग और कुछ विशेष पौधे 'फॉग हार्वेस्टर' जालों के जरिए इस कोहरे से पानी इकट्ठा करते हैं। सहारा जैसे रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म होते हैं, लेकिन अटाकामा का तापमान साल भर काफी सुहावना (औसतन 18°C से 22°C) रहता है, हालांकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े तांबे और लिथियम के भंडारों में से एक है। अत्यधिक सूखे के कारण, यहाँ के कुछ हिस्सों में बैक्टीरिया तक जीवित नहीं रह पाते, जो इसे सहारा या थार की तुलना में अधिक बंजर बनाता है।

अटाकामा अपनी 'परग्रही' (Alien-like) बनावट के कारण पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ग के समान है। हमारे प्रिय ब्लॉगरों के वीडियोस के जरिए हमने कई स्थलों को देखा। वैली ऑफ द मून (Valle de la Luna) की चट्टानें और नमक के ऊँचे टीले बिल्कुल चंद्रमा की सतह जैसे दिखते हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा अद्भुत होता है। एल टाटियो गीजर (El Tatio Geysers) दुनिया के सबसे ऊँचे गीजर क्षेत्रों में से एक है, जहाँ सुबह-सवेरे जमीन से गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। तारामंडल और खगोल विज्ञान के लिए उपयुक्त साफ़ आसमान और प्रदूषण मुक्त वातावरण के कारण अटाकामा स्टारगेजिंग (Stargazing) के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीनें (जैसे ALMA) स्थित हैं। हाथ की विशाल आकृति (Mano del Desierto) जो रेगिस्तान के बीचों-बीच बनी हुई है पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। साइकिल बाबा डॉ राज यहां अपनी साइकिल को इसी मूर्ति के पास खड़ा कर कैंप लगाकर पूरी रात इस निर्जन स्थल पर बिताते हैं और सुबह की किरणों के साथ सुंदर सूर्योदय के दर्शन करा देते हैं।

ये सच है कि चिली जैसे दूरस्थ देश तक पहुंचना ही किसी भारतीय आम पर्यटक के लिए बहुत कठिन और खर्चीला होता है। लेकिन घुमक्कड़ों के माध्यम से यहां की आभासी सैर भी बहुत कुछ जानने समझने का अवसर तो दे ही देती है।

महावीर जयंती पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।

सत्य, तप और संयम की शाश्वत संहिता

महावीर का जन्म होते ही उनके पिता राजा सिद्धार्थ के राज्य, मान-प्रतिष्ठा और धन-धान्य में वृद्धि होने लगी थी, इसीलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया था और चूंकि वर्धमान बचपन से ही बड़े साहसी व निर्भीक थे, इसीलिए उनके पराक्रम के कारण आगे चलकर वे महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज के परिवेश में हम जिस प्रकार की समस्याओं और जटिल परिस्थितियों में घिरे हैं, उन सभी का समाधान महावीर के सिद्धांतों और दर्शन में समाहित है। भगवान महावीर कहा करते थे कि जिस जन्म में कोई भी जीव जैसा कर्म करेगा, भविष्य में उसे वैसा ही फल मिलेगा। वह कर्मानुसार ही देव, मनुष्य, नारक व पशु-पक्षी की योनि में भ्रमण करेगा। कर्म स्वयं प्रेरित होकर आत्मा को नहीं लगते बल्कि आत्मा कर्मों को आकृष्ट करती है। वह कहते थे कि रूग्णजनों की सेवा-सुश्रुषा करने का कार्य प्रभु की परिचर्या से भी बढ़कर है। अपने जीवनकाल में उन्होंने ऐसे अनेक उपदेश और अमृत वचन दिए, जिन्हें अपने जीवन तथा आचरण में अमल में लाकर हम अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं।

प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया जाता है। महावीर जयंती इस वर्ष 31 मार्च को मनाई जा रही है। जैन धर्म के जानकारों के अनुसार भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर के राजघराने में हुआ था। भगवान महावीर ने जीवन पर्यन्त अपने अमृत वचनों से समस्त मानव जाति को ऐसी अनुपम सौगात दी, जिन पर अमल करके मानव चाहे तो इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। 'अहिंसा परमो धर्मः' सिद्धांत के लिए जाने जाते रहे भगवान महावीर का अहिंसा दर्शन आज के समय में सर्वाधिक प्रासंगिक और जरूरी प्रतीत होता है क्योंकि वर्तमान समय में मानव अपने स्वार्थ के वशीभूत कोई भी अनुचित कार्य करने और अपने फायदे के लिए हिंसा के लिए भी तत्पर दिखाई देता है।

महावीर का जन्म होते ही उनके पिता राजा सिद्धार्थ के राज्य, मान-प्रतिष्ठा और धन-धान्य में वृद्धि होने लगी थी, इसीलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया था और चूंकि वर्धमान बचपन से ही बड़े साहसी व निर्भीक थे, इसीलिए उनके पराक्रम के कारण आगे चलकर वे महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज के परिवेश में हम जिस प्रकार की समस्याओं और जटिल परिस्थितियों में घिरे हैं, उन सभी का समाधान महावीर के सिद्धांतों और दर्शन में समाहित है। भगवान महावीर कहा करते थे कि जिस जन्म में कोई भी जीव जैसा कर्म करेगा, भविष्य में उसे वैसा ही फल मिलेगा। वह कर्मानुसार ही देव, मनुष्य, नारक व पशु-पक्षी की योनि में भ्रमण करेगा। कर्म स्वयं प्रेरित होकर आत्मा को नहीं लगते बल्कि आत्मा कर्मों को आकृष्ट करती है। वह कहते थे कि रूग्णजनों की सेवा-सुश्रुषा करने का कार्य प्रभु की परिचर्या से भी बढ़कर है। अपने जीवनकाल में उन्होंने ऐसे अनेक उपदेश और अमृत वचन दिए, जिन्हें अपने जीवन तथा आचरण में अमल में लाकर हम अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं।

भगवान महावीर का कहना था कि जो मनुष्य स्वयं प्राणियों की हिंसा करता है या दूसरों से हिंसा करवाता है अथवा हिंसा करने वालों का समर्थन करता है, वह जगत में अपने लिए बैर बढ़ाता है। अहिंसा की तुलना संसार के सबसे महान व्रत से करते हुए उनका कहना था कि संसार के सभी प्राणी बराबर हैं, अतः हिंसा को त्यागिए

और 'जीओ व जीने दो' का सिद्धांत अपनाइए। वे कहते थे कि संसार में प्रत्येक जीव अवध्य है, अतः आवश्यक बताकर की जाने वाली हिंसा भी हिंसा ही है और वह जीवन की कमजोरी है। उनके अनुसार छोटे-बड़े किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, बिना दी गई वस्तु स्वयं न लेना, विश्वासघाती असत्य न बोलना, यह आत्मा निग्रह सद्पुरूषों का धर्म है। जो लोग कष्ट में धैर्य को स्थिर नहीं रख पाते, वे अहिंसा की साधना नहीं कर सकते। अहिंसक व्यक्ति तो अपने से शत्रुता रखने वालों को भी अपना प्रिय मानता है। उनका कहना था कि संसार में रहने वाले चल और स्थावर जीवों पर मन, वचन एवं शरीर से किसी भी तरह के दण्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर के अनुसार किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही ज्ञानी होने का एकमात्र सार है और यही अहिंसा का विज्ञान है। जिस प्रकार अणु से छोटी कोई वस्तु नहीं और आकाश से बड़ा कोई पदार्थ नहीं, उसी प्रकार अहिंसा के समान संसार में कोई महान् व्रत नहीं। महावीर के शब्दों में कहें तो ज्ञानी होने का यही एक सार है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे और यही अहिंसा का विज्ञान है।

धर्म को लेकर भगवान महावीर का मत था कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है और अहिंसा, तप व संयम उसके प्रमुख लक्षण हैं। जिन व्यक्तियों का मन सदैव धर्म में रहता है, उन्हें देव भी नमस्कार करते हैं। अपने प्रवचनों में वह कहते थे कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद यदि कर्म श्रेष्ठ हैं तो वही व्यक्ति ब्राह्मण है किन्तु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि वह हिंसाजन्य कार्य करता है तो वह ब्राह्मण नहीं है जबकि नीच कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर सुआचरण, सुविचार एवं सुकृत्य करता है तो वह बाह्मण है। आत्मा के बारे में भगवान महावीर का तर्क था कि आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा चेतन है, आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है। उनका कहना था कि मानव और पशुओं के समान पेड़-पौधों, अग्नि, वायु में भी आत्मा वास करती है और पेड़ पौधों में भी मनुष्य के समान दुख अनुभव करने की शक्ति होती है। महावीर कहते थे कि क्रोध प्रेम का नाश करता है, मान विषय का, माया मित्रता का नाश करती है और लालच सभी गुणों का। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उसे पाप को बढ़ाने वाले इन चारों दोषों क्रोध, मान, माया और लालच का त्याग कर देना चाहिए।

विचार

ध्रुव शुक्ल

लेखक साहित्यकार हैं।

भारत माता रोज़ मेरे पास आकर कहती है

माता रोज़ मेरे पास आकर कहती है कि... राज्य पाने का लोभ ऐसी राजनीतिक स्पर्धा को बढ़ाता जा रहा है कि जिससे बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय और सद्भाव का मान प्रतिदिन घट रहा है। राजनीतिक गठबंधन अपने बाड़ों में विभाजित करके उस बहुविश्वासी जीवन को बेचैन किये हुए हैं जो अभावग्रस्त होने के बावजूद भी प्रेम और आपसी सहयोग के मूल्य को अब तक बचाये हुए है। राज्य की नीतियॉं देश के जीवन को ऐसे बाज़ार में अकेला क्यों छोड़ रही हैं जहॉं वह दौड़-दौड़कर थक रहा है, हार रहा है?

भारत माता रोज़ मेरे पास आकर कहती है कि... पूरा देश भयानक शोर से क्यों भरता जा रहा है और देश के जीवन में बीतता समय गहरी ऊब में क्यों डूबा हुआ है? देश के मन में इतनी गहरी अशांति क्यों भरती जा रही है कि किसी को उससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं सूझ रहा? लगता है कि कोई अपनी तरफ देख ही नहीं रहा। सबने इतना ज़्यादा दूसरापन पैदा कर लिया है कि उन्हें दूसरों पर दोष मढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। वे एक-दूसरे को कलंकित कर रहे हैं और देश में ग़ैर जिम्मेदार जीवन का अमित विस्तार हो रहा है। सब दूसरों पर आक्षेप लगाकर वही करते रहते हैं जो वे दूसरों को करने नहीं देना चाहते। इस तरह सब एक-दूसरे की नज़रों में संदिग्ध होते जा रहे हैं। देश के जीवन में विश्वस्नीयता और प्रसन्नता घट रही है। जैसे सब एक-दूसरे के प्रति अविश्वास से भरकर अप्रसन्न जीवन काट रहे हैं।

माता रोज़ मेरे पास आकर कहती है कि... राज्य पाने का लोभ ऐसी राजनीतिक स्पर्धा को बढ़ाता जा रहा है कि जिससे बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय और सद्भाव का मान प्रतिदिन घट रहा है। राजनीतिक गठबंधन अपने बाड़ों में विभाजित करके उस बहुविश्वासी जीवन को बेचैन किये हुए हैं जो अभावग्रस्त होने के बावजूद भी प्रेम और आपसी सहयोग के मूल्य को अब तक बचाये हुए है। राज्य की नीतियॉं देश के जीवन को ऐसे बाज़ार में अकेला क्यों छोड़ रही हैं जहॉं वह दौड़-दौड़कर थक रहा है, हार रहा है?

भारत माता रोज़ मेरे पास आकर कहती है कि... बाज़ार और राजनीति के विज्ञापन आपस में इतने घुले-मिले लग रहे हैं जैसे राजनीति सेवा नहीं, कोई धंधा हो। देश में दब्बू ग़रीबी और अराजक अमीरी फ़ैल रही है। करोड़ों लोग तो ऐसे भी देखने में आते हैं जिन्हें सबेरा होते ही यह मालूम नहीं होता कि आज रोटी कैसे मिलेगी!

भारत माता रोज़ मेरे पास आकर कहती कि... कोई ईश्वर नहीं है पर तुम तो हो। तुम्हें ये जल,जंगल,ज़मीन और जानवर प्रकृति से मिले हैं और तुम ही इसके न्यासी हो। फिर क्यों तुम अपने जन्म सिद्ध स्वराज्य को प्रमाणित करने में विफल होकर परराज्य में शरण खोज रहे हो? तुम तो जनम-जनम से एक-दूसरे पर आश्रित हो फिर यह अपनापन क्यों भूल जाते हो? तुम्हारी यह पार्टनरशिप तो जन्म-जन्मांतर से चली आ रही है फिर तुम क्यों अपने जीवन और उसके साधनों को सदियों से फिरंगी लुटेरों का जरिया बना रहे हो?

भारत माता रोज़ मेरे पास आकर कहती हैं कि... जीवन के ज्ञान को देश-काल के अनुरूप सँवारते

रहना चाहिए। फिर जीवन बार-बार नया होकर जी उठता है। जीवन किसी अतीत का खण्डहर नहीं, वह तो सतत वर्तमान है। वर्तमान को सँवारते रहने से ही जीवन हर देश-काल में फूलता-फलता रहता है। यह सागर के झाग से उछली हुई बूँद जैसा जीवन नहीं जानता कि उसकी मृत्यु किस विधि से आती है पर वह जीते-जी अपने आपको सौन्दर्य प्रदान करने के ज्ञानात्मक उपाय करता ही रहता है। सब अकेले मरते हैं पर जीने की कला तो परस्पर आश्रित है। सारा जीवन अन्तरनिर्भर है।

भारत माता रोज़ मेरे पास आकर कहती हैं कि... दुनिया में ज्ञानोपदेश के कई पर्वत शिखर भी हैं और कई प्रकार की ज्ञान मीमांसा उन पर्वतों पर ज्ञान की खदानों जैसी है जिनमें खुद से रौशन ज्ञानप्रकाश छिपा हुआ है। उन खदानों का रहस्य जीवन के मर्म में डूबे लोग ही जानते हैं। (कपटवेशधारी लुटेरे नहीं।) उन खदानों का पता अपने ही ज्ञानरूपी नेत्रों से पाया जा सकता है। अव्यभिचारिणी और शांत बुद्धि ही इन ज्ञान की खदानों को खोदने की कुदाल है। जो लोग ज्ञान प्रकाश को अपने हृदय की गहराई में प्रेम से खोजते हैं, उन्हें वह मिलता है। वह मैले तेल से भरे अंधेरे कुओं में नहीं मिल सकता।

भारत माता रोज़ मेरे पास आकर कहती है कि... हमारी सभ्यता एक वट वृक्ष जैसी है। जिसकी घनी शाखाओं पर बरन-बरन के पंछी अपने घोंसलें बनाकर रहते हैं। उनके कलरव से भारत में भोर होती है और जब तक वे अपने नीड़ पर न लौट आयें तब तक उनकी प्रतीक्षा में शाम ठहरी रहती है। ऋतुकालों में दूर देश से आने वाले प्रवासी पंछी भारत की राह नहीं भूले हैं। वे यहॉं की आब-ओ-हवा को अपनी संतानों के जन्म के लिए अनुकूल पाते हैं।

भारत माता रोज़ मेरे पास आकर कहती है कि... बीती सदियों में फिरंगी लुटेरों ने इस वट वृक्ष जैसी सभ्यता की जड़ें खोद-खोदकर देखीं पर उनका ओर-छोर उन्हें नहीं मिला। प्रकाश की ओर ऊँचा उठा यह वृक्ष अब तक मुरझाया नहीं। हार-थककर फिरंगी लौट गये पर तुम न जाने क्यों उन उघरी हुई जड़ों पर माटी डालकर उन्हें मूँदना भूल गये। वे जड़ें सूखती रहीं। इस वट वृक्ष की छाया अभी भी इतनी कम तो नहीं हो गयी है कि उससे कोई बाहर रह जाये। अगर तुम उसकी जड़ों में खाद-पानी डालते रह सको तो वह हरा-भरा होकर अपनी आत्मीय छाया को सब पर फैलाकर बचा रह सकेगा।

भारत माता रोज़ मेरे पास आकर कहती है कि... भारत सब धर्मों का देश कहलाने के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हें सदियों से यह सुअवसर मिला हुआ है कि सिर्फ़ मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के हित में अपने-अपने धर्म की खूबियों को निरन्तर विकसित करो। सभी धर्मों की इस सामुदायिकता से ऐसी आधुनिक जन स्मृति रची जा सकती है जो भारत ही नहीं, पूरे विश्व की नागरिक संहिता का दर्जा पा सके।

सार्वजनिक जीवन में आचरण और व्यवहार मर्यादित होना चाहिए

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

इस समय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपेक्षा सोशल मीडिया में तमाम छोटे-बड़े राजनेताओं के व्यभिचार के किस्सों पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कहीं-कहीं तो कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक तौर पर लब्ध प्रतिष्ठित शख्सियत के चाल चलन, चरित्र और व्यवहार पर गहरा आक्षेप तक व्यक्त कर दिया गया है। वैसे तो प्रिंट मीडिया और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तमाम तरह के मसालेदार समाचारों को अपनी गरिमा एवं जिम्मेदारी के भाव के साथ प्रकाशित या प्रसारित करता है। लेकिन सोशल मीडिया में कब, कहां, कौन, किसको निशाने पर धर लेवे, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

नई पीढ़ी का रुझान तो तकनीकी विकास एवं विस्तार के चलते प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया पर भी काफी हद तक विश्वास से भरा होता है। जिसके चलते आए दिन अलग-अलग क्षेत्र की लब्ध प्रतिष्ठित शख्सियत को निशाने पर लिए जाने के चलते जनमानस के किसी कोने में संदेह का बीज भी अंकुरित हो जाता है। कभी-कभी तो सोशल मीडिया में अधूरा सच राजनीतिक और सामाजिक ही नहीं अपितु स्थापित धार्मिक शख्सियत को भी लपेटे में ले लिया करता है। कल्पना कीजिए जब एक स्थापित शख्सियत को लेकर ऊलजुलूल टिप्पणी कर दी जाए, फिर चाहे उसका खेद प्रकट कर दिया जाए। लेकिन तीर तो निशाने पर लग चुका होता है, जिसका घाव निशान छोड़ देता है।

इन संदर्भों में यह अत्यंत आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों को अपने आचरण और व्यवहार में शुचिता और पवित्रता को आत्मसात करना चाहिए। यह ठीक है कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों की भी अपनी संविधान सम्मत कुछ स्वतंत्रता भी होती है। लेकिन अपने चरित्र पर कोई दाग न लगने पाए, ऐसा आचरण और व्यवहार भी अपेक्षित होता है। दरअसल आजकल के दौर में आम आदमी का व्यक्तिगत जीवन भी किसी से अछूता नहीं रह गया है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली शख्सियत को तो अपने और अपने क्षेत्र के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए एक प्रकार से पारदर्शी व्यक्तित्व का परिचय देना ही चाहिए।

आजकल हर तरह की घटनाएं पलक झपकते ही जाने किस-किस के संज्ञान में आ जाया करती है। जिसके चलते जहां सकारात्मक बातों का भी संदेश जाता है तो नकारात्मक बातों का भी गहरा संदेश जाता है। इसके चलते एक सकारात्मक बात की अपेक्षा नकारात्मक मुद्दों को ही अधिक हवा मिलने लगती है। जिसका परिणाम यह होता है कि जिन्हें अपने दामन पर दाग न लगने देना हो, वह भूल कर भी राजनीतिक या सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने को उत्सुक नहीं रहता। यह स्थिति राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र को असामाजिक वर्ग के लिए खुला छोड़ देती है। यही नहीं अपितु निकट भविष्य में भयावह परिणाम का कारक भी हो सकती है। ऐसे में भला कौन मानुष सार्वजनिक जीवन को अपनाएगा ?

इसके अतिरिक्त एक गहन चिंता का विषय यह भी है कि जो शख्सियत सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होती है, फिर चाहे वह राजनीति में हो या समाज सेवा में, उनके दामन पर लगता दाग राजनीति और समाज के साथ-साथ आम आदमी के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। हालांकि व्यभिचार जैसे मामलों की स्थिति एकपक्षीय ही हो, यह आवश्यक नहीं है। वैसे भी परस्पर सहमति से बहुतेरे व्यभिचार आजकल के दौर में व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय शख्सियत अपनी स्वतंत्रता को उच्छृंखलता का जामा पहने दें।

आजकल के दौर में किसी का व्यक्तिगत जीवन भी कितना उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है, इस बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाली शख्सियत को तो भ्रष्ट आचरण अथवा कामवासना से कोसों दूर ही रहना चाहिए। दरअसल यह एक जग जाहिर तथ्य है कि किसी भी किस्म का किया गया अपराध या दूषित आचरण और व्यवहार अपने जीवन काल में नहीं तो जीवन काल के बाद भी उदय में आ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में अपनी सक्रियता को एक प्रकार से घोर तपस्या के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने महामृत्युंजय मंदिर में की पूजा

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा शहर में किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर पहुंचकर भगवान शंकर के दर्शन किये और पूजा-अर्चना कर प्रदेश वासियों के कल्याण की कामना की।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने प्राकृतिक खेती का लिया जायजा

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा के हरिहरपुर स्थित खेत में प्राकृतिक खेती द्वारा उगाये जा रहे साग-सब्जी और गेहूं की फसल का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निरीक्षण के दौरान जैविक इनपुट, मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण एवं रासायनिक मुक्त खेती की प्रक्रियाओं का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत रत्न सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई की स्मृति में सुशासन भवन में फोटो गैलरी का शुभारंभ किया।

एमपी में हर दूसरा व्यक्ति ले रहा मुफ्त का राशन

9 करोड़ की आबादी में 5.38 करोड़ लोग सरकारी अनाज के भरोसे

भोपाल (नप्र)। एमपी की आधे से ज्यादा आबादी मुफ्त का अनाज ले रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5,38,07,137 लोग मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं।

यह आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि राज्य की कुल अनुमानित आबादी (लगभग 9 करोड़) के लिहाज से देखें तो करीब 60त्न आबादी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह सरकारी मदद पर निर्भर है । यानी राज्य का हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति आज गरीब कल्याण योजना का हितग्राही है।

नीति आयोग की रिपोर्ट में 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए- नीति आयोग की जनवरी 2024 में जारी भारत में बहुआयामी गरीबी (मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया) रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 9 सालों (2013-14 से 2022-23) के दौरान मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।

एक तरफ जहां सरकार का दावा है कि 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ 25 मार्च 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि एमपी के 5.38 करोड़ लोग आज भी मुफ्त राशन पर निर्भर हैं।

देश के 80 करोड़ गरीबों में एमपी की बड़ी हिस्सेदारी

राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को देखें तो पूरे देश में कुल 79,40,02,614 लोग इस योजना के दायरे में हैं। इस बड़ी संख्या में अकेले मध्य प्रदेश के लाभार्थियों की हिस्सेदारी 6.78 है । उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश देश का पांचवां सबसे बड़ा राज्य है जहां मुफ्त राशन लेने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है।

नर्मदापुरम की पल्लवी ने धार्मिक ग्रंथों को रिवर्स राइटिंग में लिखा

25 साल की मेहनत के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

नर्मदापुरम (नप्र)। रिवर्स राइटिंग में नर्मदापुरम की बेटी ने नया रेकॉर्ड बनाया है। इस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर पूरे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। इसके लिए पल्लवी चौकसे ने 25 वर्षों तक साधना की है। इसके बाद उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डस 2026 में दर्ज किया गया है। उन्होंने रिवर्स राइटिंग की प्रैक्टिस साल 2000 से शुरू की थी।

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम

दरअसल, पल्लवी चौकसे का नाम मिरर इमेज लेखन के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 में दर्ज हुआ है। पल्लवी ने वर्ष 2000 से पढ़ाई के दौरान सामान्य और उल्टे अक्षरों में लिखने का अभ्यास शुरू किया। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा को उनके पिता अरुण पारे ने पहचाना और लगातार प्रोत्साहित किया। वहीं, उनकी माता अलका पारे से मिले संस्कारों ने उनकी कला को आध्यात्मिक दिशा दी।

महान ग्रंथों को उल्टा लिखा

उन्होंने महान ग्रंथों को 'उल्टा' लिखने का अद्भुत कारनामा पिछले ढाई दशकों में किया है। पल्लवी ने कठिन साधना के साथ कई प्रमुख धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों को रिवर्स राइटिंग में लिखा है, जिनमें श्रीरामचरितमानस, श्रीमद्भगवद्गीता, मधुशाला और बाइबिल शामिल हैं। यह उपलब्धि अपने आप में दुर्लभ और प्रेरणादायक मानी जा रही है। पल्लवी अपनी उपलब्धि का श्रेय सत्य साईं बाबा की कृपा को देती हैं। उनके जीवन का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब उनके द्वारा रिवर्स राइटिंग में लिखित श्रीरामचरितमानस को साईं बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप स्पर्श किया। पल्लवी इसे अपनी साधना का सबसे बड़ा प्रतिफल मानती हैं। मैं 2000 से रिवर्स राइटिंग कर रही हूं। पहले ऐसे ही लिखती थी। फिर मेरे पिता ने कहा कि इस विद्या को आगे बढ़ाओं और कुछ बड़ा लिखो। मैंने इसके बाद ग्रंथों को उल्टा लिखना शुरू कर दी। यह 25 वर्षों की मेरी साधना है।

उन्होंने कहा कि अभी भी मैं इसके लिए कुछ समय देती हूं। यह मेरी लिए बड़ी उपलब्धि है। पल्लवी चौकसे की उपलब्धि पर परिवार में खुशी की लहर है। साथ ही परिवार का कहना है कि उसकी मेहनत को यह सम्मान मिला है।

रीवा में 60 वर्षीय महिला को धारदार हथियार से काटा

पुलिस को सिर्फ धड़ मिला, सिर अभी भी गायब; इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

रीवा (नप्र)। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सोमवार दोपहर एक 60 वर्षीय महिला का सिर कटा शव मिला है। मामला लोही गांव का है, जो बिछिया थाना क्षेत्र में आता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। मृतक की पहचान लीला पटेल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार महिला का शव धड़ से अलग अवस्था में मिला है, जबकि सिर अभी तक बरामद नहीं हो सका है। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। एसपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि सिर कटा शव मिलने के मामले में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। संभावित सुराग जुटाने की कोशिश जारी है, ताकि घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

मप्र में पार्वती-चंबल-कालीसिंध सहित छह परियोजनाएं अब 15,794 करोड़ रुपये में होंगी पूरी

भोपाल, नप्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा नियंत्रण मंडल और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में रविवार को पार्वती-चंबल-कालीसिंध सहित छह सिंचाई परियोजनाओं को पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई। 15,794 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

प्रदेश की सबसे लंबी 11.952 किलोमीटर की स्लीमनाबाद टनल (जल सुरंग) का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। जल्द ही उद्घाटन कार्यक्रम होगा। बैठक में बताया गया कि बरगी व्यपवर्तन परियोजना पर बीते दो वर्ष में तेजी से काम पूरे किए गए। स्लीमनाबाद टनल के निर्माण का काम 85 प्रतिशत हो गया है। इसका पूरा होने पर 1.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इस टनल के राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल्वे लाइनों, भूमिगत क्रासिंग और आबादी क्षेत्र इत्यादि के नीचे से सुरक्षित गुजरते हुए संरचना को कोई क्षति नहीं पहुंची। बैठक में पार्वती-चंबल-कालीसिंध सहित विभिन्न सिंचाई परियोजना की लागत पुनरीक्षित करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी डॉ. राजेश राजौरा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

महावीर जयंती के अवकाश के चलते आईडीए बजट अब आज पेश होगा

इस बजट में शहर के यातायात सुधार पर खास जोर दिया जाएगा

इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) का सोमवार सुबह प्रस्तुत होने वाला बजट अचानक एक दिन के लिए टाल दिया गया। महावीर जयंती के अवकाश को लेकर हुई घोषणा के चलते यह निर्णय लेना पड़ा। रविवार शाम को महावीर जयंती के अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई।

आईडीए का बजट सोमवार सुबह 10 बजे संचालक मंडल की बैठक में पेश होना तय था और इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। यहां तक कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ परीक्षित झाड़े के बीच बजट को लेकर चर्चा भी हो चुकी थी। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग दिन अवकाश घोषित किए जा रहे थे। इंदौर में भी संशय बना रहा, लेकिन देर रात कलेक्टर शिवम वर्मा ने आदेश जारी कर सोमवार को ही महावीर जयंती का अवकाश घोषित कर दिया।

अवकाश की घोषणा होते ही आईडीए ने भी तत्काल सूचना जारी कर दी कि संचालक मंडल की बैठक अब मंगलवार सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी। अब एक दिन की देरी के बाद मंगलवार को बजट पेश होगा,जिसमें शहर के आगामी विकास कार्यों की दिशा और प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी। फिलहाल प्राधिकरण का संचालन पूरी तरह अधिकारियों के हाथों में है।

बड़ी सौगात की उम्मीद

इस बजट में शहरवासियों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद की गई। इसमें धार रोड स्थित चंदन नगर के पास एक नए फ्लायओवर ब्रिज का प्रस्ताव सबसे अहम रहेगा। ब्रिज निर्माण के साथ कई एजेंडे भी रखे जाएंगे। प्रस्तावित योजना के अनुसार चंदन नगर चौराहे से जिला अस्पताल तक लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से फ्लायओवर ब्रिज का प्रस्ताव रखा जाना लगभग तय है। इसका निर्माण नगर निगम द्वारा किया जाएगा, जबकि प्राधिकरण इसे डिपॉजिट वर्क के रूप में पूरा करेगा।

मेजर रोड को प्राथमिकता

शहर के पूर्वी हिस्से में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित मेजर रोड 11 और मेजर रोड 12 को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इन सड़कों का काम पिछले साल शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। खासतौर पर मेजर रोड 12 के निर्माण में बड़ी झुग्गी बस्ती बाधा बनी हुई है, जहां 1000 से ज्यादा मकान हैं। इसके अलावा बड़ा गणपति चौराहा और मरीमाता चौराहा पर पहले से प्रस्तावित फ्लायओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को भी इस वित्तीय वर्ष में शुरू करने की योजना है। वहीं, राजीव गांधी चौराहे पर भी फ्लायओवर बनाने की मांग तेज हो गई है। कुल मिलाकर, इस बजट में शहर के यातायात सुधार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया।

निगम टीम से मारपीट करने वालों पर केस

इंदौर। शनिवार दोपहर परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब मोबाइल कोर्ट की टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। मालवा मिल चौराहे से पाटनीपुरा रोड तक चल रही इस कार्रवाई के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया और भीड़ ने टीम के वाहनों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा कि रिमूव्हल विभाग के अधिकारी बेकरी गली में कार्रवाई कर रहे थे, जबकि उनके वाहन पास ही खड़े थे। इसी दौरान महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया, इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए।

देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और वाहनों की ओर बढ़ गई। आरोप है कि भीड़ ने वाहन को घेर लिया और स्वास्थ्य अधिकारी की गाड़ी को भी रोक लिया। इस दौरान ड्राइवर कैलाश अग्रवाल के साथ गाली-गलौज की गई। गाड़ी की चाबी निकाल ली गई और वाहन का साइड ग्लास तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज कर लिया है।

नेग के नाम पर किन्नरों का उत्पात

इंदौर। तुलसी नगर के ए-सेक्टर (सरस्वती माता मंदिर के पास) में नेग मांगने आए किन्नरों द्वारा जमकर उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। 51 हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने घर में घुसकर धमकियां दीं और हंगामा किया। घटना के मुताबिक बैंक मैनेजर आशीष दुबे के घर बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे सात किन्नर पहुंचे। उस समय घर में उनकी मां और पत्नी मौजूद थीं। परिवार ने पहले 5100 और फिर 11 हजार रुपये देने की बात कही, लेकिन किन्नर अड़ गए और जबरदस्ती घर में घुस आए।

आरोप है कि उन्होंने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी,जिससे घबराकर मां बच्चे को लेकर कमरे में बंद हो गईं। किन्नरों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की। वृद्धा के साथ अभद्रता करते हुए मंदिर की मूर्ति तक फेंक दी गई। शोर सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो उनसे भी दुर्व्यवहार किया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। घटना सीसीटीवी में कैद है। रविवार को हुई बैठक में किन्नर गुरु ने माफी मांगी।

महिला ने बेटी की सगाई टूटने का बदला इस तरह लिया

महिला के कहने पर पहले बाइक चुराई, फिर कार में आग लगाई

इंदौर। बदमाश ने 15 हजार रुपए के लालच में पहले फरियादी की बाइक चुराई, फिर उसी बाइक से जाकर कार में भी आग लगा दी। बदमाश ने महिला के कहने पर वारदात की। वारदात के बाद वह देवास भाग गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

विजयनगर थाने में 16 मार्च को फरियादी कपिल चौहान निवासी विजयनगर ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उसकी वेगनार कार (एमपी 09 डब्ल्यूई 6887) घर के बाहर खड़ी थी। दूसरे दिन जब उसने देखा तो कार जली अवस्था में मिली। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 350 सीसीटीवी कैमरे चेक कर फुटेज खंगाले। इसमें एक युवक का हुलिया कार को आग लगाते दिखा। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किए और तकनीकी साक्ष्य से आरोपी की तलाश शुरू की। इसी बीच, मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी अजय चौहान निवासी देवास को निरंजनपुर से पकड़ा।

लंबे समय से ही पहचान

पुलिस के अनुसार, महिला और आरोपी की लंबे समय से पहचान है। आरोपी महिला के कहने पर कई वारदात कर चुका है। महिला भी उससे मिलने और वारदात कराने देवास जाती रही है। पुलिस दोनों आरोपियों के रिकार्ड खंगाल रही है।

सगाई टूटने से महिला नाराज

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे कार में आग लगने के लिए मनीषा अग्रवाल निवासी इंदौर ने 15 हजार रुपए दिए थे। महिला की बेटी की सगाई फरियादी के छोटे भाई के साथ तय हुई थी। लेकिन, किसी कारण शादी नहीं हो पाई। इसी से महिला फरियादी से नाराज होकर बदला लेना चाहती थी। महिला ने कुछ दिन पहले आरोपी को पैसे देकर फरियादी की बाइक चोरी कराई थी। इसी बाइक से बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने षड्यंत्रकारी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया।

फर्नीचर दुकानों में आग, कारण अस्पष्ट

इंदौर। एबी रोड स्थित रीजनल पार्क के आगे फर्नीचर की दो दुकानों में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दोनों दुकानें जलकर खाक हो गईं। हादसे में लाखों रुपए का फर्नीचर नष्ट हो गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 4:15 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही 10 मिनट के भीतर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जांच की जा रही है।

बताया जा रहा है कि यहां संजय और विजय नाम के दो सगे भाई फर्नीचर का कारोबार करते हैं। दोनों की दुकानें पास-पास शेड बनाकर संचालित की जा रही थीं। लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरा सामान चपेट में आ गया। दमकलकर्मियों ने करीब 27 हजार लीटर से ज्यादा पानी डालकर आग पर काबू पाया। इसके अलावा नगर निगम के टैंकर ने भी पास के पंप से पानी लाकर मदद की।

विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है

प्रधान जिला न्यायाधीश शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी- कलेक्टर श्री विश्वकर्मा, जिला न्यायालय परिसर में मेगा लीगल आउटरीच एंड अवेयरनेस कैंप एवं वृहद विधिक सेवा प्रदर्शनी का आयोजन

रायसेन,(निप्र)। रायसेन में जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा आयोजित मेगा लीगल आउटरीच एंड अवेयरनेस कैंप एवं वृहद विधिक सेवा प्रदर्शनी का प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सोहाने, कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा तथा पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष ने कहा कि 'न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। ऐसे शिविरों के माध्यम से आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकें।' उन्होंने आगे कहा कि 'मध्यस्थता विवादों के समाधान का एक सरल, त्वरित एवं प्रभावी माध्यम है। मध्यस्थता 2.0 अभियान के तहत लोगों को न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से विवाद निपटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे समय एवं संसाधनों की बचत होती है।' साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की कि वे नालसा एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा किसी भी विधिक समस्या के समाधान हेतु निःसंकोच प्राधिकरण से संपर्क करें। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी- कलेक्टर श्री विश्वकर्मा कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि 'शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तभी सार्थक है जब उसकी जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ऐसे विधिक जागरूकता शिविर नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि 'प्रशासन सदैव आमजन के हित में कार्यरत है और विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर समाज के कमजोर वर्गों तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।' नागरिकों को कानून की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है- पुलिस अधीक्षक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा कि 'कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों को कानून की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज का निर्माण करते हैं।'

उन्होंने आगे कहा कि 'मध्यस्थता एवं आपसी संवाद के माध्यम से कई विवादों का समाधान बिना न्यायालय गए ही संभव है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।' उक्त क्रम में श्री कमलेश कुमार इटावदिया, तृतीय जिला न्यायाधीष रायसेन, श्री सचिन जैन, प्रथम जिला न्यायाधीष रायसेन, श्री अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री जी.एस. मेहन्देले श्रम पदाधिकारी, श्री विनोद भोसले जिला समन्वयक आदिम जाति कल्याण विभाग रायसेन, श्री अजय सक्सेना चीफ लीगल एड डिफेंस कार्उंसिल, श्री आनंद नेमा ब्लाक समन्वयक जन अभियान परिषद, श्री एच.बी. सेन संचालक केएसएस, श्री अतुल जाट उत्कर्ष नशा मुक्ति केंद्र सांची जिला रायसेन एवं श्रीमती प्रगति रैकवार पैरालीगल वालेंटियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। शिविर का मुख्य उद्देश्य इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को निःशुल्क विधिक परामर्श उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा विभिन्न शासकीय विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। साथ ही, मध्यस्थता 2.0 अभियान एवं सामुदायिक मध्यस्थता के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं तहसील मुख्यालय के समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता, एनजीओ के सदस्य उपस्थित रहे। वृहद विधिक सेवा प्रदर्शनी का आयोजन कार्यक्रम में शासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां नागरिकों को उनके अधिकारों, कानूनी प्रक्रियाओं एवं शासन की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित विधिक विशेषज्ञों द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें उचित विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उक्त विधिक सेवा प्रदर्षनी का माननीय प्रधान जिला न्यायाधीष महोदय, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर आवष्यक दिषा-निर्देष सम्प्रसारित किए गए। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता, शासकीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने एवं सशक्त बनने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती हर्षिणी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा किया गया। उनके द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक संख्या में ऐसे आयोजनों में भाग लेकर निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ उठाएं। कार्यक्रम के अंत में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन द्वारा सभी अतिथियों, विभागीय अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का संक्षिप्त समापन किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि 'इस प्रकार के विधिक जागरूकता शिविरों का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन निरंतर किए जाते रहेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।'

संक्षिप्त समाचार

विजय भवन में निशुल्क योग कक्षा शुरू हुई

बैतूल,(निप्र)। रामनवमी के अवसर पर भारत स्वाभिमान न्यास द्वारा गंज स्थित जिला कार्यालय में योग, यज्ञ एवं गुरुदक्षिणा-समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के प्राकट्य पर्व और योगऋषि स्वामी रामदेव के संन्यास दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में किया, जिसमें बड़ी संख्या में योग साधकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया। जिला प्रभारी सुनील कुबड़े ने बताया विजय भवन में निशुल्क योग कक्षा शुरू की। यह कक्षा प्रतिदिन सुबह 5:30 से 7 बजे तक संचालित होगी, जिसमें सभी नागरिकों से शामिल होने की अपील की है।

कैम्पस ड्राइव में 119 विद्यार्थियों का प्राथमिक चयन हुआ

हरदा,(निप्र)। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 27 व 28 मार्च को पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में डैकिन एसी कम्पनी की दो दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अभिरुचि सिंह ने बताया शनिवार को कैंपस ड्राइव में हरदा, बैतूल और खंडवा के डिप्लोमा अंतिम वर्ष के 147 विद्यार्थियो ने भाग लिया। ट्रेनिंग प्लेसमेंट अधिकारी विकास भुमरकर ने बताया कि इस दौरान राजस्थान और आंध्रा में स्थित प्लांट के लिए कुल 119 विद्यार्थियों का प्रारंभिक चयन हुआ।

हरदा में नलकूप खनन पर प्रतिबंध:कलेक्टर ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक लगाई रोक

हरदा,(निप्र)। हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक या पर्याप्त वर्षा होने तक प्रभावी रहेगा। यह निर्णय आगामी ग्रीष्मकाल में भू-जल स्तर में संभावित गिरावट को देखते हुए लिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड हरदा के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि हरदा जिले में पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान भू-जल स्तर 39.8 मीटर है। अत्यधिक गर्मी और तापमान में वृद्धि के कारण भू-जल स्तर में और गिरावट आने की आशंका है। पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और जल स्रोतों को प्रभावित होने से बचाने के लिए यह कदम आवश्यक माना गया है। कलेक्टर जैन ने मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और (संशोधित) अधिनियम 2022 की धारा 3 के तहत हरदा जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। इस आदेश के तहत, संपूर्ण हरदा जिले में नए निजी नलकूपों और हैंडपंपों के खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त, बिना सक्षम अनुमति के जल स्रोतों से कृषि और औद्योगिक कार्यों के लिए सिंचाई पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। नलकूप खनन या सिंचाई की अनुमति जारी करने के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अधिकृत किए गए हैं।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जल संरक्षण और संवर्धन हेतु किए जा रहे हैं कार्य

रायसेन,(निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जल संरक्षण और संवर्धन हेतु किए जा रहे हैं कार्य रायसेन, 28 मार्च 2026 प्रदेश के साथ ही रायसेन जिले में भी 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 का शुभारंभ हो गया है। आगामी 30 जून 2026 तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु आमजन को जागरूक करने के साथ ही जल संरचनाओं की सफाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बेगमगंज तहसील के पिपलिया बरई में जागरूकता रैली निकालकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। बाड़ी जनपद के चैनपुर में अमृत सरोवर में सामूहिक श्रमदान कर साफ सफाई की गई। अभियान के तहत रायसेन जिले में भी मुख्यतः जन-जागरूकता अभियान, नवीन जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण, भू-जल संवर्धन, पहले से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं की साफ-सफाई, मरम्मत, जल वितरण प्रणालियों की साफ-सफाई, राजस्व रिकार्ड में जल संग्रहण संरचनाओं को अंकित करने का कार्य प्राथमिकता से कराया जा रहा है। जिले में बनाये गये जलदूतों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता अभियान में सुनिश्चित की जा रही है।

राजस्व मंत्री ने इछावर सिविल अस्पताल में नवीन मंडपम का किया लोकार्पण

सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है - राजस्व मंत्री श्री वर्मा

सीहोर,(निप्र)। राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने इछावर सिविल अस्पताल में नवनिर्मित पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा मंडपम का लोकार्पण किया। यह मंडपम डॉ वीवी शर्मा द्वारा अपने पिता श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मरीजों के परिजनों के बैठने एवं आराम के लिए बनवाया गया है, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को सुविधा होगी।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और मरीजों के साथ आने वाले परिजनों की सुविधा का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि मरीजों के उपचार की व्यवस्था करना। उन्होंने कहा कि पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा मंडपम का निर्माण एक सराहनीय पहल है, जो मानवता और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है तथा आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य है है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सामाजिक सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार लाया जा सकता है। इस अवसर पर इछावर नगर परिषद अध्यक्ष श्री देवेंद्र वर्मा, डॉ वीवी शर्मा और सीबीएमओ डॉ अंकित चांडक सहित अन्य अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित थे।

विदिशा में 5 दिवसीय भूकंप पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण संपन्न, 100 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

विदिशा,(निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन एवं एडीएम श्री अनिल कुमार डामोर के मार्गदर्शन में पांच दिवसीय भूकंप पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ श्री मयंक कुमार जैन ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार संपादित कार्यों की जानकारी देते हुए बताया है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग इकाई विदिशा के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय भूकंप पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन होटल अर्श पैलेस में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इनमें महाविद्यालयों के प्राचार्य, एनसीसी, एनएसएस, 'माय भारत', सिविल डिफेंस, जनपद पंचायत, नगर पालिका, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी, निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि, पुलिस विभाग, होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ के सदस्य शामिल रहे। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन की मूलभूत जानकारी, भूकंप से बचाव के उपाय तथा आपातकालीन परिस्थितियों में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही विभिन्न आपदा प्रबंधन उपकरणों का प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) कर उनके उपयोग की व्यावहारिक जानकारी भी दी गई, जिससे प्रतिभागियों की आपदा से निपटने की क्षमता में वृद्धि हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ श्री मयंक कुमार जैन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी के रूप में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड श्री मयंक कुमार जैन तथा सहायक नोडल अधिकारी एवं प्रशिक्षक प्लाटून कमांडर सुश्री रश्मि दुबे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल शक्ति से नव भक्ति कार्यक्रम आयोजित

सीहोर,(निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम छतरी, रायपुरा और मुहाली में 'जल शक्ति से नव भक्ति' कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वृक्ष एवं जल स्त्रोतों का पूजन कर जल एवं प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया और ग्रामवासियों को जल और प्रकृति के संरक्षण के प्रेरित किया गया। कार्यक्रम ब्लॉक समन्वयक श्री प्रदीप सिंह सेंगर ने जल मंदिर की स्थापना, प्रभात फेरी, कलश यात्रा, भूमि पूजन, भजन संध्या, दीपमाला, देवी गीत, संकीर्तन, आरती, जल प्रबंधन एवं नर्सरी स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ग्रामवासियों को बताया कि इस अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है, इसलिए हम का यह दायित्व है कि हम आगे आकर जल स्त्रोंतो और पेड़ों का संरक्षण करें और इस अभियान को सफल बनाएं।

एचपीवी टीकाकरण को लेकर सख्त निर्देश, करैयाखेड़ा शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर लक्ष्य पूर्ण करने पर जोर

विदिशा,(निप्र)। विदिशा शहरी स्वास्थ्य केंद्र करैयाखेड़ा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी शहरी आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आरबीएसके टीम को निर्देशित किया गया है कि वे अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण हेतु प्रेरित कर केंद्र पर लाएं और टीकाकरण सुनिश्चित करें। जारी निर्देशों में कहा गया है कि करैयाखेड़ा स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र में एचपीवी वैक्सीनेशन सेंटर संचालित है, जहां पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। सभी फील्ड कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से संपर्क कर पात्र बालिकाओं एवं महिलाओं को चिन्हित करने तथा उन्हें समय पर केंद्र तक लाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता को निर्धारित लक्ष्य (टार्गेट) के अनुरूप कार्य करना है और समय सीमा में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कहा कि एचपीवी टीकाकरण महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस अभियान को गंभीरता से लिया जाए।

विदिशा में अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्यवाही, 12 वाहन जप्त

विदिशा,(निप्र)। संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा गठित राज्य स्तरीय दल ने जिला विदिशा में 24 से 27 मार्च तक सघन निरीक्षण अभियान चलाकर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जिले की सभी 16 रेत खदानों का मौके पर निरीक्षण किया गया, जिससे खनन गतिविधियों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। निरीक्षण के दौरान टीम ने अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए खनिजों का अवैध परिवहन करते 11 वाहन (डम्पर एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली) तथा अवैध उत्खनन करते 01 वाहन (ट्रैक्टर-ट्रॉली) को जप्त किया। इस प्रकार कुल 12 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जो प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है।

जप्त किए गए वाहनों को संबंधित पुलिस थाना कुरवाई, शहर बासोदा, गुलाबगंज, देहात बासोदा, कुरवाई एवं खनिज कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखवाया गया है। सभी मामलों में विधिवत प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं। जिला खनिज अधिकारी श्री प्रशांत तिवारी ने बताया है कि संबंधित वाहन संचालकों एवं

अवैध उत्खननध्परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इन प्रकरणों को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां आगे की वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। भविष्य में भी इस प्रकार के सघन निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे, ताकि खनिज संपदा की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

1 अप्रैल से ई-टोकन से ही मिलेगा खाद

बैतूल ,(निप्र)। जायद मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा समीक्षा की गई। बैठक में कृषि, उद्यानिकी एवं सिंचाई विभाग के जिला अधिकारी तथा मैदानी अमला उपस्थित रहा। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 5981 ई-टोकन जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से किसानों को 3448.59 मीट्रिक टन खाद वितरित किया गया है। उर्वरक वितरण में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से ई-टोकन के माध्यम से ही खाद वितरण अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने विभागीय तैयारियों की विकासखंडवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसानों को व्हाट्सएप एवं संदेश के माध्यम से लघु फिल्म के जरिए ई-टोकन जारी करने की प्रक्रिया समझाई जाए। साथ ही पटवारी, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, समिति प्रबंधक, डबल लॉक केंद्र प्रभारी, यूथ सर्वेयर एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं का सहयोग सुनिश्चित किया जाए। जिन किसानों के सभी सर्वे नंबर एग्रिस्टेक आईडी से लिंक नहीं हैं, उनके आवेदन ई-विकास प्रणाली के माध्यम से कराए जाएं, ताकि किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

नरवाई जलाने पर सख्ती के निर्देश

बैठक में जिले में पुन : नरवाई जलाने की घटनाओं पर बताया गया कि तकनीक के माध्यम से अक्षांश-देशांतर के आधार पर संबंधित खेत की पहचान तुरंत हो जाती है। ऐसे मामलों में प्रकरण दर्ज कर पर्यावरण क्षति के विरुद्ध नियमानुसार दंड वसूली की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्देश दिए कि हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य किया जाए। ऐसा न पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कृषकों को नरवाई से खाद बनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए। जिन क्षेत्रों में नरवाई जलाने के प्रकरण सामने आएंगे, वहां के कृषि विस्तार अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि सरसों की खरीदी 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि सरसों की रीसाइक्लिंग न हो, किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिले और मसूर एवं चना उपार्जन में किसी प्रकार की समस्या न आए।

जहां बाघ का शिकार, वहां एक एकड़ में अफीम लगी, 700 से ज्यादा पौधों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए

नर्मदापुरम,(निप्र)। छिंदवाड़ा जिले के तामिया के पास स्थित छातीआम गांव में बाघ की हत्या के मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस खेत में एसटीआर के बाघ को यूरिया देकर मारा गया था, वहीं पर चोरी-छिपे अफीम की खेती भी की जा रही है। मौके पर बड़ी संख्या में अफीम के पौधे पाए गए, जिन्हें देखकर वन विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। वन विभाग ने इसकी सूचना तामिया थाने को भी दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस मामले में वन विभाग की मॉनिटरिंग टीम की लापरवाही भी सामने आई है। बाघ के रेडियो कॉलर से 3 मार्च से कोई हलचल नहीं मिल रही थी, लेकिन टीम 23 दिन बाद लोकेशन के आधार पर जांच के लिए पहुंची, तब जाकर शिकार का मामला सामने आया। खेत में करीब एक एकड़ में 700 से ज्यादा

अफीम के पौधे मिले हैं। पौधों में डोडा आ चुके हैं, जिनमें चीरा लगे हैं। संभवतः अफीम निकलनी शुरू हो गई है। कुछ दिन बाद पौधे खसखस निकलने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपए तक हो सकती है। खुलासे के बाद भी अधिकारियों के बयान स्पष्ट नहीं हैं। छिंदवाड़ा डीएफओ साहिल गर्ग का कहना है कि जानकारी पुलिस को दी जा रही है। वहीं, छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने बताया कि फॉरेस्ट विभाग से जानकारी मिली है, इसमें टीम मौके पर जाकर जांच कराई जाएगी। जांच में जो बिंदु सामने आएंगे उसे पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आशंका है कि देरी के कारण अफीम की खेती के सबूत मिटाए जा सकते हैं। मामले में नारकोटिक्स विभाग को भी सूचना देने की जरूरत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह बाघ एसटीआर के देनवा बफर और छिंदवाड़ा पश्चिम वनमंडल के सांगाखेड़ा क्षेत्र में घूमता था। छातीआम के रहने वाले आरोपी उदेसिंग (50) के खेत में बाघ पहले मवेशी का शिकार भी कर चुका था। ऐसे में आशंका है कि बाघ के बार-बार खेत में आने से किसान को हमले का डर होगा। पौधों से अफीम निकालने में अड़चन आ रही होगी। इसलिए उसने बाघ को मारा होगा। हालांकि आरोपियों ने पूछताछ में मवेशियों के मरने से नाराजगी के चलते बाघ को यूरिया देकर हत्या करने की बात स्वीकार की है।

डेढ़ साल पहले बांधवगढ़ से लाया गया बाघ मृत मिला : एसटीआर क्षेत्र संचालक राखी नंदा ने बताया कि बाघ की उम्र करीब 4 साल थी और उसे डेढ़ साल पहले बांधवगढ़ से लाकर यहां छोड़ा गया था। वह लंबे समय से इसी इलाके में रह रहा था। एसटीआर फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बाघ कॉलर आईडी निकालने के लिए विभाग को पत्र लिखा था। बाघ की आखिरी लोकेशन के आधार पर 26 मार्च को टीम छातीआम गांव पहुंची। जांच के दौरान एक मृत बैल मिला, जिससे शक बढ़ा।

सर्चिंग के दौरान डॉग स्क्वॉड आरोपी के घर जाकर रुका : इसके बाद डॉग स्क्वॉड की मदद ली गई। एसटीआर की डॉग अपोलो और छिंदवाड़ा फॉरेस्ट से डॉग स्कूबी को बुलाया। सर्चिंग के दौरान टीम आरोपी उदेसिंग के घर तक पहुंची, जहां पूछताछ में उसने शिकार की बात कबूल कर ली। जंगल में करीब 200 मीटर दूर एक गड्ढे से बाघ का शव बरामद किया गया, जिसे मारकर दफनाया गया था। पोस्टमॉर्टम में जहर से मौत की पुष्टि हुई है। इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी उदेसिंग के अलावा बिसनलाल, मनोहर सिंह, कैलाल और मनक सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।

मॉनिटरिंग में लापरवाही का आरोप, जांच

राइट क्लिक

लॉक डाउनः सिर्फ सियासी शोशेबाजी या भावी संकट की 'पब्लिक टेस्टिंग'?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

उधर पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध अपने दौर में प्रवेश कर रहा है तो इधर भारत में राजनीतिक शोशों और लोगों में डर पैदा करने की नई मिसाइलें चल रही हैं। इसका ताजा उदाहरण वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते भारत भर में लॉक डाउन लगने की आशंका का है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ अफवाह है, ऐसे किसी विचार पर बात नहीं हो रही है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का तर्क यह है कि इस बार कोई घातक वायरस भले न हो, लेकिन ईंधन का गंभीर संकट समूची आर्थिकी को लकवाग्रस्त कर देगा। यानी पर्याप्त ईंधन ही नहीं होगा तो सारी गतिविधियां खुद-ब-खुद ठप हो जाएंगी। अघोषित लॉक डाउन लग जाएगा। इस संदर्भ में सरकार की सफाई है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कुछ विपक्षी नेता एक काल्पनिक आशंका को हकीकत से जोड़ने पर आमादा हैं। हालांकि जो आम लोग वास्तव में परेशान हैं, उनकी चिंता सिर्फ इतनी है कि ईंधन की सुलभता वाले दिन कब लौटेंगे। याद करें वही 'लॉक डाउन,' जो देश में कोरोना प्रकोप के दौरान लगा था और जिसकी याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। 'लॉक डाउन' वह भौतिक और मानसिक स्थिति है, जिसमें लगभग सब कुछ थम जाता है, सिवाय इंसान की सांसों के। यानी संचार बंद, सामाजिक संवाद बंद, कार्यस्थलों पर कामकाज बंद, सामूहिक गतिविधियां बंद। एक जबरन थोपा गया एकांतिक जीवन, जिसे जिंदा रहने के लिए जरूरी माना गया हो। तब लॉक डाउन चरणों में लगा था और पहले दौर ने लोगों की रोजी-रोटी तक छीन ली थी। हालांकि दूसरे, दौर में सरकार ने कुछ आर्थिक गतिविधियों को छूट दी थी।

बहरहाल, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में यूं तो भारत की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, लेकिन हम उसकी आंच में तेजी से झुलस रहे हैं। इसमें हमारा रोल कुल इतना है कि हम सबसे संपर्क में हैं और किसी तरह अपने जहाज निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जंग से हमारे आयात के साथ निर्यात पर भी बुरा असर पड़ रहा है। युद्ध लंबा चला तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। तो क्या इसी आशंका के चलते 'लॉक डाउन' का शिगूफा छोड़ा गया है? सवाल यह भी है कि लोगों से सचेत रहने की सरकारी चेतावनियों के बीच 'लॉक डाउन' की बात आई कहां से, ऐसी बात को हवा देने के पीछे मकसद क्या है, क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि कोरोना काल की तरह फिर लॉकडाउन लगाया जाए? और सच में लगे तो इससे देश का कितना नुकसान होगा? यदि लॉक डाउन की बात केवल सियासी शोशेबाजी है तो फिर इसका सियासी लाभ किसके खाते में जा सकता है, साथ में यह भी कि क्या ऐसा करना देश विरोधी नहीं है?

केवल युद्ध के कारण किसी देश में लॉक डाउन लगा हो, ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं है, उन देशों में भी नहीं, जो सीधे युद्धों में उलझे हैं। लॉक डाउन असाधारण आपात सामाजिक स्थिति है, जब संचार पर पूरी तरह ताले पड़ जाते हैं और दूरियां रखने को ही जिंदा रहने की गारंटी मान लिया जाता है। आज से 6 साल पहले समूची दनिया में एक नए और खतरनाक वायरस कोरोना महामारी के कारण ऐसी स्थिति बनी थी। कोविड 19 वायरस मानव स्पर्श से फैलता था और फेफड़ों पर हमला कर व्यक्ति की जान ले लेता था। लिहाजा आइसोलेशन ही बचने का सॉल्यूशन माना गया। एक विचित्र स्थिति पैदा हुई, जब 'सामाजिक प्राणी' कहलाने वाले मनुष्य को ज्यादा से असामाजिक होने पर विवश किया गया। लेकिन आज तो वैसी स्थिति नहीं है।

याद रहे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते 24 मार्च 2020 की रात आठ बजे कोरोना प्रकोप के कारण पूरे देश में 21 दिन के लॉक डाउन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि लोग यह भूल जाएं कि घर से बाहर निकलना क्या होता है। तब तक देश में कोरोना वायरस के 519 मामलों की पुष्टि हो चुकी थी और नौ लोगों की मौत भी हो चुकी थी। संयोग से इस घटनाक्रम के एक माह पहले ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। और अब ईरान-अमेरिका युद्ध के केन्द्र में भी वो और नेतन्याहू हैं।

दरअसल लॉक डाउन का यह ताजा 'वायरस' हाल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद फैला, जिसमें उन्होंने मास्को में उद्योगपतियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ईरान-इजरायल युद्ध के कारण दुनिया भर में आर्थिक मंदी और कोरोना जैसी स्थिति जैसे-ईंधन की कमी पैदा होने का अंदेशा है। जिसके परिणाम कोरोना महामारी की तरह हो सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर लॉकडाउन लगने जैसी बात नहीं कही। लेकिन पुतिन का इतना चेताना भी भारत में चुनावी चूल्हे में आग फूंकने के लिए काफी था। चुनावग्रस्त पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने तत्काल इसे तत्काल उछालते हुए कहा कि देश में केन्द्र सरकार देश में लॉकडाउन लगा सकती है और लोग घरों में बंद हो सकते हैं। इसी संदर्भ में 2021 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाते हुए ममता ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद उनकी पार्टी ने सभी पाबंदियों के बावजूद चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से जीती। पार्टी अब किसी भी परिस्थिति में फिर से तैयार रहेगी। इसमे यह संदेश छुपा था कि अगर लॉक डाउन लगा तो यह टीएमसी के फायदे में ही होगा। यानी यहां लॉक डाउन की आशंका से ज्यादा उसकी चाहत है। ममता के बयान को कुछ दूसरे विपक्षी नेताओं ने और सुलगाने की कोशिश की और बतौर सबूत पेट्रोल पंपों पर और गैस एजेंसियों पर लगी लोगों की लंबी लाइनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जाने लगीं। ममता तो अब यह भी कह रही हैं कि उनकी जान लेने की साजिश की जा रही है।

यहां कॉमन बात यह है कि प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कोविड संकट का जिक्र किया और ममता बैनर्जी ने भी कोविड लॉक डाउन का हॉरर सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की। यह संयोग है या फिर एक भावी गंभीर संकट की 'पब्लिक टेस्टिंग' यही सवाल आज लोगों के मन को मथ रहा है। हालांकि संकेतों में कही गई बात को लोगों ने देश की भाग्य रेखाओं से जोड़ दिया तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसका मजाक भी बनाया। अलबत्ता कोविड और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक संकट में एक समानता है, वो ये कि दोनो के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिट होगी। इसकी शुरूआत हो भी चुकी है, क्योंकि युद्धआ की समाप्ति के कोई लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं।

भारत की राजनीतिक शतरंज में एक मुद्दा और उछल रहा है, वो है इस वैश्विक संकट में भारत द्वारा म्ध्यशस्थता का। कहा जा रहा है कि चूंकि भारत के सभी से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए हमे सभी पक्षों के बीच सुलह के लिए मध्यएस्थता करनी चाहिए। बात सही है। लेकिन कोई भी मध्यस्थता तभी सफल होती है, जब सम्बन्धित पक्षों का उस पर विश्वास हो। साथ ही सभी पक्ष अपने रूख को लेकर स्पष्ट और ईमानदार हों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नितांत अगंभीर, अस्थिर और अविश्वनीअय रवैये के चलते कौन-सा देश (पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, उसकी अपनी मजबूरियां हैं) मध्यस्थ बनने का जोखिम लेगा? दूसरे, इस देश में अफवाहों पर 'लॉक डाउन' कौन लगाना चाहता है, क्योंकि इसके मंडन और खंडन के भी अपने सियासी फायदे हैं, जो राजनीतिक दलों की नजर में देशहित से ज्यादा जरूरी हैं।

राज्य सरकार प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने उपलब्ध करा रही है सहयोग और मार्गदर्शन

एमएसएमई इकाइयां औद्योगिक गतिविधियों का प्रभावी केन्द्र और लाखों परिवारों के स्वावलंबन का हैं आधार : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश, देश के सर्वाधिक सशक्त, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले प्रथम तीन राज्यों में से एक है। राज्य सरकार प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है। देश-दुनिया के सभी निवेशकों के लिए प्रदेश के दरवाजे खुले हैं। हम उद्योग मित्र नीतियों और सहयोग की भावना के साथ उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग हो या कृषि हर क्षेत्र में योगदान के लिए निरंतर सक्रिय है। एमएसएमई इकाइयां औद्योगिक गतिविधियों का प्रभावी केन्द्र होने के साथ लाखों परिवारों के स्वावलंबन का आधार भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को समर्थ एमएसएमई विकसित मध्यप्रदेश की थीम पर मुख्यमंत्री निवास में 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को उनके खाते में 169.57 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से जारी कर संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्टार्टअप को लगभग 28 लाख से अधिक की अनुदान राशि की प्रथम किश्त भी जारी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने लघु उद्योग निगम की ओर से 8 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश का चैक भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैतूल और आगर-मालवा के तीन उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के लिए आवंटन-पत्र प्रदान किए और मुख्यमत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत हितलाभ वितरण भी किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज का आयोजन महावीर जयंती के शुभ अवसर पर हो रहा है। यह भगवान महावीर के जनकल्याण और शुचिता के सिद्धांतों को साकार करने का भी प्रतीक है। प्रदेश में उद्योग-व्यापार गतिविधि और उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करते हुए निरंतर नवाचार जारी हैं। राज्य सरकार उद्यमियों को लिए पूंजी, भूमि और व्यवस्थाओं में सरलता कर, उनकी प्रगति की राह को आसान बना रही है। विभाग द्वारा बड़ी राशि का सिंगल क्लिक से सीधे अंतरण व्यवस्था में सुगमता और स्पष्टता का परिचायक है। पूरे देश में मार्च क्लोजिंग का वातावरण है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों और उद्यमियों को राशि और सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह प्रदेश में नए संकल्पों के साथ नया वित्तीय वर्ष आरंभ करने का भी प्रतीक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भी प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही भारत स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर है। युद्ध के दोनों पक्ष भारत का सहयोग कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री श्री मोदी की कुशल नीतियों से ही संभव है। जहां एक ओर विश्व के कई देशों में पेट्रोल-डीजल, गैस की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, वहीं हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इनके मूल्यों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत समर्थ भी है और सक्षम भी।

सभी क्षेत्रों में हो रही है प्रगति : मंत्री काश्यप

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनता के बीच सक्रिय होने के साथ प्रशासनिक दृष्टि से भी निरंतर गतिशील हैं। उनके व्यापक और स्पष्ट दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप प्रदेश उद्योग-व्यापार, कृषि, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। प्रमुख सचिव श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में विभाग में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। जिसके परिणामस्वरूप भूमि आवंटन प्रक्रिया को गति मिली है। प्रदेश के 25 औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य जारी हैं, साथ ही 6 नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 7100 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं।

मंदसौर-बैतूल में बारिश, नीमच में गिरे ओले

भोपाल में बदला मौसम, तेज हवा के साथ बूंदाबांदी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में सोमवार को मौसम ने अचानक तेज रुख ले लिया है। बैतूल, मैहर, श्योपुर, मंदसौर और नीमच में तेज बारिश हो रही है, जबकि नीमच में ओले गिरे हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और धार में बादल छाए हुए थे। भोपाल में देर शाम तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई कई जगह पानी की तेज बौछारें भी पड़ी। ऐसा मौसम अगले 3 से 4 दिनों तक

सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने 6 जिलों में आंधी के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इनमें खंडवा, बैतूल, देवास, नीमच, श्योपुर और खरगोन शामिल हैं। वहीं 10 से ज्यादा जिलों में बारिश-आंधी का असर देखने को मिलेगा। इनमें छिंदवाड़ा, रतलाम, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा और अनूपपुर (अमरकंटक) में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन से बदला मौसम

मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी, पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम में यह बदलाव आया है। रविवार को ग्वालियर समेत कई जिलों में बादल और हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई थी, जो इस सिस्टम के सक्रिय होने का संकेत था। यह सिस्टम 30 मार्च से प्रभावी होकर पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रहा है और सागर, रीवा और शहडोल संभाग समेत अधिकांश इलाकों में 2 अप्रैल तक मौसम बदला रहेगा।

'बेटा' सुनते ही भड़का बदमाश चाकू घोंपकर कारोबारी की हत्या

भोपाल में अपने कर्मचारियों को छोड़ने गया था, रास्ते में विवाद के दौरान समझा रहा था

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में मामूली विवाद ने रविवार देर रात खौफनाक रूप ले लिया। 'बेटा' कहकर समझाने की कोशिश करने पर आरोपियों ने 35 साल के चाय कारोबारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी।

सोमवार सुबह गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने सुभाष कॉलोनी में चक्काजाम कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद करीब आधे घंटे में जाम खुल सका। इस दौरान परिजन का पुलिस से विवाद भी हुआ। परिजन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ थाना परिसर में प्रदर्शन किया।

इधर, हमीदिया अस्पताल की मॉर्चुरी के सामने भी मृतक के परिजन ने हंगामा किया था। यहां पुलिस बल तैनात किया गया है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी अनुराग लाल ने बताया कि मामूली विवाद में हत्या हुई है। तीन संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ बम फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

होटल बंद कर लौट रहा था, रास्ते में हुआ विवाद- पुलिस के मुताबिक, मृतक विजय मेवाड़ा सुभाष कॉलोनी का रहने वाला था। वह अशोका गार्डन और कोलार इलाके में चाय की दो होटल चलाता था। रविवार देर रात करीब 1:30 बजे वह होटल बंद कर कर्मचारियों को छोड़ने प्रगति नगर गया था।

यहां मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ बम अपने साथियों फरमान, कालू और इमरान के साथ बैठा था। सभी मृतक के कर्मचारियों के पुराने दोस्त बताए जा रहे हैं।

आरोपियों ने कर्मचारियों को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सुबह जल्दी काम होने का हवाला देकर मना कर दिया। इस पर आरोपियों ने उनसे अभद्रता शुरू कर दी। विजय ने इसका विरोध किया। उसने आसिफ को 'बेटा' कहकर समझाने की कोशिश की। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। पुलिस के अनुसार, गुस्साए आसिफ ने चाकू निकालकर विजय के पेट में घोंप दिया। उसके साथियों ने भी मारपीट की। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल विजय को कर्मचारी और स्थानीय लोग फौरन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

नशे में लड़कियों के बीच सड़क पर झगड़ा

एमपी नगर में रात का 'हाई वोल्टेज ड्रामा, बाल पकड़कर घूसे मारे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एमपी नगर जोन-2 इलाके में रविवार देर रात सड़क पर कुछ युवतियों के बीच जमकर विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें युवतियां आपस में झगड़ती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सभी युवतियां नशे की हालत में थीं और किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। घटना को लेकर यह भी चर्चा है कि झगड़े के दौरान एक युवक की उंगली में गंभीर चोट आई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एमपी नगर थाना प्रभारी जय हिंद शर्मा के अनुसार इस मामले में थाने में न तो कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और न ही एफआरबी में कोई कॉल या घटनाक्रम दर्ज हुआ है।

चॉकलेट में निकला कॉकरोच और फफूंद

बदबू आने पर परिवार को दिखाई, कहा- ये लापरवाही गंभीर, शिकायत करेंगे

जबलपुर (नप्र)। नामी ब्रांड की चॉकलेट में भी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहपुरा-भिटौनी इलाके में एक 14 वर्षीय छात्र द्वारा खरीदी गई कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट में कॉकरोच और फफूंद मिलने का मामला सामने आया है।

कक्षा 8वीं के छात्र अंश सेन ने पास की किराना दुकान से रू. 55 की चॉकलेट खरीदी थी। घर पहुंचकर जैसे ही उसने रैपर खोला, चॉकलेट में मरा हुआ कॉकरोच, उसके अंडे और फफूंद दिखाई दी। साथ ही उसमें से बदबू भी आ रही थी। अंश ने तुरंत यह चॉकलेट अपने परिवार को दिखाई।

परिजनों के मुताबिक, चॉकलेट के पैकेट पर एक्सपायरी डेट 8 जून 2026 अंकित है। यानी उत्पाद अभी वैध अवधि में था, फिर भी उसमें खराबी मिली।

रिटायरमेंट के बाद साहब की 'जनसेवा' की तमन्ना

मध्य प्रदेश में चुनाव भले ही 2028 में हों, लेकिन कुछ आईएएस अधिकारी मिजाज ए सियासी होने के लिए कुलांचे मारने लगे हैं। मालवा के आदिवासी अंचल से आने वाले एक 'प्रमोटी साहब' के दिल में राजनीति का प्रेम उमड़ रहा है। रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े इन महोदय को

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

अब सरकारी बंगले से ज्यादा विधानसभा की कुर्सी सुरक्षित नजर आ रही है। फिलहाल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तैनात ये अधिकारी महोदय आदिवासी संगठन के अपने पुराने रसूख को भुनाने की तैयारी में हैं। चर्चा तो यह भी है कि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल इन पर डोरे डाल रहे हैं, क्योंकि 'वोट बैंक' की चाबी जो उनके पास है। देखना दिलचस्प होगा कि साहब की ये राजनीतिक 'लॉन्चिंग' सफल होती है या फिर 'पावर' के खेल में उनका दांव उलटा पड़ जाता है।

मेरे वाले और तेरे वाले में अटके एल्डरमैन

प्रदेश के 16 नगर निगमों में एल्डरमैन बनने का सपना संजोए बैठे नेताओं की धड़कनें अब 'वेटिंग लिस्ट' पर टिक गई हैं। खबर है कि नगर पालिकाओं में तो 150 एल्डरमैन की रेवड़ियां बंट गईं, लेकिन नगर निगमों की बारी आते ही पेंच फंस गया। वजह वही पुरानी-'मेरे वाले' और 'तेरे वाले' की जंग! प्रदेश के आधा दर्जन बड़े नगर निगमों में स्थानीय क्षत्रपों के बीच ऐसी खींचतान मची है कि मामला सीधे हाईकमान की चौखट पर जा पहुंचा है। आलम यह है कि प्रदेश नेतृत्व ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। अब चर्चा है कि पहले 'प्रदेश कार्य समिति' की जंबो लिस्ट आएगी, उसके बाद ही इन 16 निगमों के भाग्य का ताला खुलेगा। यानी, जब तक बड़े साहबों का मन नहीं मिलता, तब तक कार्यकर्ताओं को 'आशीर्वाद' के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।

आपदा में अवसर, अब बनेगी मुसीबत

मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक ऐसी 'महारानी' के चर्चे हैं, जिन्होंने टीवी स्क्रीन पर तो अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाते हुए 50 लाख रुपये जीते थे, लेकिन लगता है कि 'कौन बनेगा करोड़पति' की उस हॉट सीट से मन नहीं भरा। अब खुलासा हो रहा है कि पिछली सरकार के दौरान जब प्रदेश बाढ़ की विभीषिका से कराह रहा था, तब ये मैडम जनता की 'राहत' में अपनी 'चाहत' ढूंढ रही थीं। विडंबना देखिए, जो अधिकारी ज्ञान की बातें कर सुर्खियां बटोरते थे, उन्होंने आपदा को अवसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाढ़ राहत के सरकारी खजाने में ऐसी सेंधमारी की गई कि अब परतें खुलने पर कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की आंच उन 'बड़ों' तक भी पहुंचेगी जो इस लूट में मूकदर्शक बने रहे या फिर छोटे प्यादों को बलि का बकरा बनाकर फाइलें बंद कर दी जाएंगी?

संविदा का 'चक्रव्यूह' : अफसरों की सिट्टी-पिट्टी गुम!

सरकारी महकमों में इन दिनों अजीब सा सन्नाटा और घबराहट है। वजह है-सवा लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का जिन्न, जो बोतल से बाहर निकल चुका है। हाईकोर्ट के सख्त आदेश और एक पूर्व आईएएस को मिली सजा ने मौजूदा साहबों की रातों की नींद उड़ा दी है। पहले तो नौकरशाही ने पदों को 'डाइंग कैडर' घोषित कर पेंच फंसाया था, ताकि परमानेंट नौकरी की राह रोकी जा सके। लेकिन अब 'माननीय अदालत' की डेडलाइन सिर पर है। एक बड़े विभाग के विभागाध्यक्ष तो इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को चिट्ठी लिखकर 'बचाओ-बचाओ' की गुहार लगाई है। तर्क यह है कि कर्मचारी हजारों में हैं और पद मुट्ठी भर! अब साहब पशोपेश में हैं कि 'संविदा नीति 2023' का पालन करें तो पद कहां से लाएं, और न करें तो कोर्ट का डंडा तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि यह फाइल अब किस रद्दी की टोकरी में जाएगी या फिर किसी की कुर्सी जाएगी!